समसामयिकी दिसम्बर 2016

हिंदी आईएएस

यूनेस्को ने योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया:-

संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने योग को दुनियाभर में प्रतिष्ठित **मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों** की सूची में शामिल कर लिया। यूनेस्को ने कहा है कि योग के दर्शन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं कला जैसे भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है।

मुख्य बिंदु

- इथोपिया के अदिस अबाबा में आयोजित यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 11वें सत्र में इस बात की औपचारिक घोषणा हुई की योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक वैश्विक विरासत के तौर पर स्वीकार किया गया है।
- प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत में योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योग एक ऐसी कला है जिसे कोई भी इंसान सीख ले तो उसके अंदर एक अनोखी ऊर्जा, एक अनोखी शक्ति भर जाती है जिससे उसके मन में एकाग्रता आ जाती है और वह आसानी से अहिंसा, भाईचारा और मानवता के पथ पर चलने को मजबूर हो जाता है।
- कोई भी इंसान अगर योग करता है तो वह कई तरह की बीमारियों से भी दूर रहता है और मानसिक तौर पर अपने आप को शांत एवं नियंत्रण में रख पता है। इसीलिए आज पूरी दुनिया ने योग का लोहा माना है क्योंकि यह एक ऐसी कला है जो सर्वगुण संपन्न है।
- यूनेस्को ने सर्वसम्मति के साथ योग को अमूर्त सांस्कृतिक वैश्विक विरासत के रूप में स्वीकार किया। यूनेस्को की बैठक में योग को अमूर्त सांस्कृतिक वैश्विक विरासत घोषित करने के लिए 100 प्रतिशत वोट मिले हैं। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में योग 12वीं भारतीय विरासत है।
- यूनेस्को के मुताबिक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों के दायरे में मौखिक परंपराओं और अभिव्यक्तियों, प्रदर्शन कला, सामाजिक रीति-रिवाज, उत्सव, ज्ञान आदि को रखा जाता है। चूंकि योग को खेल की विधा माना जाता था, इसलिए इसे इस लिस्ट में शामिल होने का मौका नहीं मिला था।

विश्व एड्स दिवस

- 1 दिसंबर 2016 को विश्व एड्स दिवस पूरे विश्वभर में मनाया गया। विश्व एड्स दिवस पर इस वर्ष का विषय था: **"हैंड्स अप फॉर # एचआईवी प्रिवेंशन"**. यह दिन इस जानलेवा रोग के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है और एचआईवी तथा एड्स की रोकथाम, उपचार और देखभाल को बढ़ावा देता है।
- इस दिवस को मनाने का मकसद है सरकारों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वयं सेवी संगठनों एवं लोगों को एड्स से बचाव और उसके इलाज को संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करना है।
- विश्व एड्स दिवस के हिस्से के तौर पर, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने यह कहते हुए कि 15 वर्ष के बच्चों के बीच संक्रमण को रोकना अधिक जरूरी है अधिक निवेश एवं बच्चों तक उपचार की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया।
- एक अनुमान के मुताविक 1981 से 2007 तक करीब 25 लाख लोगों की मृत्यु एच आई बी सक्रमण के कारण हो गई। 2007 में लगभग दो लाख लोग इस महामारी से संक्रमित हुऐ।
- चुकि युवा ही नहीं हर उम्र का व्ययक्ति इस बीमारी से पीडित होने लगा इस लिए सभी उम्र और वर्ग के लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष प्रोग्राम आयोजित किये गये जिसमें हर वर्ष की एक अलग थीम बनाई गयी 1988 में विश्वन एड्स दिवस अभियान की थीम का नाम **"संचार"** था। 2007 के बाद से विश्वो एड्स दिवस को व्हाइट हाऊस द्वारा एड्स रिवन (AIDS ribbon) का एक प्रतीक देकर शुरू किया गया।

टीमइंडस का चन्द्रमा पर पहला निजी अंतरिक्ष यान :

- भारत की एक प्राइवेट स्पेस टेक्नॉलजी कंपनी टीमइंडस ,इसरो के साथ मिलकर अंतरिक्ष में एक बड़ा कदम रखने जा रही है। टीमइंडस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ मिलकर चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारने का कॉन्ट्रेक्ट साइन किया है। इसके साथ ही चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन जाएगी।
- यह प्रॉजेक्ट गूगल लूनर एक्सप्राइज की वैश्विक चुनौती का हिस्सा है जिसमें टीमइंडस इकलौती भारतीय कंपनी है। लूनर एक्सप्राइज के तहत चांद की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने, 500 मीटर तक चलाने और फोटो, विडियो पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए लगभग 204 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलेगी।
- टीमइंडस इस प्रॉजेक्ट पर 2011 से काम कर रहे हैं। वह पोलर सैटेलाइट लॉन्ट वीइकल (PSLV) के जरिए चांद पर अपना अंतरिक्ष यान दिसंबर 2017 में भेजेंगे।

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ति दिवस

- 03 दिसंबर 2016 को विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ति दिवस मनाया गया। इस दिवस का विषय था – **इच्छुक भविष्य के लिए 17 लक्ष्यों की प्राप्ति**। वर्ष 2016 में इसका लक्ष्य दिव्यांग लोगों के अधिकारों की पूर्ति करना है। इस दिवस का उद्देश्य दिव्यांग लोगों के बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत रहना भी है।
- वर्ष 2016 का अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ति दिवस सीआरपीडी एडॉप्शन दिवस की 10वीं वर्षगांठ के साथ ही मनाया जा रहा है। सीआरपीडी संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू की गयी सबसे अधिक देशों द्वारा स्वीकृत संधि है।

पृष्ठभूमि

- हर साल 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और 1992 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे अंतरराष्ट्रीय रीति-रिवीज़ के रुप में प्रचारित किया जा रहा है।
- दिव्यांगों के प्रति सामाजिक कलंक को मिटाने और उनके जीवन के तौर-तरीकों को और बेहतर बनाने के लिये उनके वास्तविक जीवन में बहुत सारी सहायता को लागू करने के द्वारा तथा उनको बढ़ावा देने के लिये साथ ही दिव्यांग लोगों के बारे में जागरुकता को बढ़ावा देने के लिये इसे सालाना मनाने के लिये इस दिन को खास महत्व दिया जाता है। 1992 से, इसे पूरी दुनिया में ढ़ेर सारी सफलता के साथ इस वर्ष तक हर साल से लगातार मनाया जा रहा है।
- समाज में उनके आत्मसम्मान, सेहत और अधिकारों को सुधारने के लिये और उनकी सहायता के लिये एक साथ होने के साथ ही लोगों की विकलांगता के मुद्दे की ओर पूरे विश्वभर की समझ को सुधारने के लिये इस दिन के उत्सव का उद्देश्य बहुत बड़ा है।
- वर्ष 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा "दिव्यांगजनों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष" के रुप में वर्ष 1981 को घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विकलांगजनों के लिये पुनरुद्धार, रोकथाम, प्रचार और बराबरी के मौकों पर जोर देने के लिये योजना बनायी गयी थी।
- सरकारी और दूसरे संगठनों के लिये निर्धारित समय-सीमा प्रस्ताव के लिये संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा "दिव्यांग व्यक्तियों के संयुक्त राष्ट्र दशक" के रुप में वर्ष 1983 से 1992 को घोषित किया गया था जिससे वो सभी अनुशंसित क्रियाकलापों को ठीक ढंग से लागू कर सकें।

भारत-क़तर सम्बन्ध:

- भारत और कतर ने 03 दिसम्बर 2016 को वीजा, साइबर स्पेस और निवेश समेत पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कतर समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच ये समझौते हुए।
- इस दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार व सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कतर की हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं में निवेश करने का इच्छुक है। राष्ट्रीय बंदरगाह प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी भारत और कतर के बीच एमओयू पर दस्तखत हुए।
- रक्षा एवं सुरक्षा, विशेषकर साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने व मनीलॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग पर रोक लगाने के लिए संयुक्त कार्रवाई पर सहमति जताई गई ।
- विशेष व आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा छूट के साथ साथ साइबर अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी सहयोग को लेकर समझौता किया गया। व्यापारियों व पर्यटकों को ई वीजा प्रदान करने के लिए समझौते पर बातचीत के बारे में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कतर करेगा, जिसके लिए भारत वहां की पुलिस को प्रशिक्षित करेगी।

क़तर से सम्बन्ध अहम

भारत के कतर के साथ घनिष्ठ और मित्रवत संबंध हैं, जो आपसी लाभप्रद व्यावसायिक आदान-प्रदान और दोनों देशों के लागों के बीच व्यापक संपर्को पर आधारित हैं। खाड़ी क्षेत्र में कतर भारत का न सिर्फ अहम व्यापारिक हिस्सेदार है, बल्कि वह सबसे ज्यादा एलएनजी की आपूर्ति भी करता है। 2015-16 में आयात कुल एलएनजी में कतर का हिस्सा 66 फीसदी रहा। इसके अलावा कतर में करीब छह लाख 30 हजार से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। कतर के विकास में भारतीयों अहम भूमिका अदा करते हैं।

रक्त पीएच सेंसर

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ने किसी भी सॉल्यूशन (विलयन) का पीएच जानने के लिए एक छोटा सा उपकरण विकसित किया है, जोकि प्रारंभिक अध्ययन में रक्त के पीएच को मापने के लिए इसकी उपयोगिता दिखा रहा है।
- पोटेंशियोमेट्रिकली रक्त का पीएच मापने की परंपरागत विधि के स्थान पर यह डिवाइस प्रतिबाधा को मापने के द्वारा काम करता है। शारीरिक पीएच रेंज में डिवाइस में संतोषजनक पीएच संवेदनशीलता पायी गयी है।
- पारंपरिक धमनी रक्त नमूना लेने के उपकरणों जोकि तीन इलेक्ट्रोड का उपयोग करने के कारण काफी भारी होते हैं तथा काफी समय खर्च कराते हैं के विपरीत यह लघु उपकरण पीएच माप के लिए शिरापरक रक्त नमूने पर निर्भर करता है।

पीएच:

- पीएच या pH, किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों (H+) की गतिविधि के सह-लघुगणक (कॉलॉगरिदम) के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- हाइड्रोजन आयन के गतिविधि गुणांक को प्रयोगात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता है, इसलिए वे सैद्धांतिक गणना पर आधारित होते हैं। pH स्केल, कोई सुनिश्चित स्केल नहीं है; इसका संबंध मानक विलयन के एक सेट (समुच्चय) के साथ होता है जिसके pH का आकलन अंतर्राष्ट्रीय संविदा के द्वारा किया जाता है।
- pH की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्ल्सबर्ग लैबॉरेट्री के डेनिश रसायनशास्त्री, सॉरेन पेडर लॉरिट्ज़ सॉरेनसेन ने प्रस्तुत किया था। शुद्ध जल को तटस्थ (न्यूट्रल) माना जाता है। 25 °से (77 °फ़ै) पर शुद्ध जल का pH, 7.0 के आस-पास होता है।

- 7 से कम pH वाले सॉलूशन को अम्लीय कहा जाता है और 7 से अधिक pH वाले सॉल्यूशन को क्षारकीय या क्षारीय कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, खाद्य विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, समुद्र विज्ञान और कई अन्य अनुप्रयोगों में pH के मापन का बहुत महत्व है।

'हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन के समापन पर अमृतसर घोषणापत्र जारी

- अमतसर में दो दिन चले हॉर्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का समापन हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमृतसर डिक्लेरेशन की घोषणा करते हुए कहा कि इस कांफ्रेंस में आतंकवाद और अलगाववाद मुख्य मुद्दा रहा। इस कांफ्रेंस में शामिल हुए 45 देशों ने अमृतसर डिक्लेरेशन को स्वीकार करते हुए एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और अफगानिस्तान के विकास में पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की।
- कांफ्रेंस में अफगानिस्तान से आतंकवाद मिटाने, अफगानिस्तान से इस रीजन के देशों की कनेक्टिविटी बढ़ाने और अफगानिस्तान के विकास में सहयोग करने के 3 मुद्दे मुख्य रूप से रखे गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कि घोषणापत्र आतंकवाद को शांति एवं स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। यह आतंकवाद के सभी रूपों और इसके सहयोग, वित्तपोषण, पनाहगाहों को फौरन खत्म करने की अपील करता है।
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जेटली ने कहा, पहली बार किसी हार्ट ऑफ एशिया घोषणापत्र में अफगानिस्तान और क्षेत्र में अलकायदा, दाएश, एलईटी तथा जेईएम जैसे आतंकी संगठनों के द्वारा की गई हिंसा पर चिंता जाहिर की गई। हालांकि, एचओए के इस्लामाबाद घोषणापत्र में अलकायदा और दाएश का जिक्र किया गया था।
- आतंकी संगठनों का मुकाबला करने के लिए समन्वित सहयोग की अपील करने के अलावा घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर काम्प्रीहेंसिव कंवेंशन को जल्द अंतिम रूप देने की मांग की गई। इसने क्षेत्रीय आतंक रोधी ढांचा के मसौदा पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों की शीघ्र बैठक किए जाने का समर्थन किया ताकि इसे जल्द अंतिम रूप दिया जा सके।
- इस साल 'हार्ट ऑफ एशिया – इस्तांबुल प्रोसेस' का विषय "चुनौतियों से निपटना, समृद्धि हासिल करना' है। हार्ट ऑफ एशिया का गठन 2011 में अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के बीच रक्षा, राजनैतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है।
- 'हार्ट ऑफ एशिया – इस्तांबूल प्रक्रिया 2011 में शुरू हुई और इसमें शामिल होने वाले देश हैं – पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अज़रबैजान, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात।

मर्कोसुर ने वेनेजुएला की सदस्यता रद्द की:

- दक्षिण अमेरिकी आर्थिक गुट मर्कोसुर ने गुट के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने और अपने बुनियादी मानकों को पूरा करने में नाकाम रहने के कारण वेनेजुएला को निलंबित कर दिया है। चार संस्थापक सदस्य देशों (अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे और पराग्वे) के विदेश मंत्रियों द्वारा वेनेजुएला की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।

वेनेजुएला को क्यों निलंबित कर दिया गया?

वेनेजुएला को इसलिए अवरुद्ध किया गया क्योंकि वर्ष 2012 में समूह में शामिल होने के बाद यह अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रहा है। तथा इसने गुट की सदस्यता के लिए आवश्यक मानकों और नियमों को पूरा करने के लिए दी गयी समयसीमा 1 दिसंबर 2016 का भी उल्लंघन किया है।
गुट ने अर्थव्यवस्था के खराब प्रदर्शन के कारण आर्थिक समूह के लिए वेनेजुएला को एक बोझ के रूप में माना है। यह छिन्न-भिन्न आर्थिक प्रणाली (दुनिया की सबसे ऊंची मुद्रास्फीति और ढहती मुद्रा), भ्रष्टाचार की समस्या से पीड़ित हैं और

नागरिक अशांति के करीब है। 2015 के बाद से, वेनेजुएला और उसके मर्कोसुर भागीदारों के बीच तनाव और बढ़ गया था।

मर्कोसुर:

- मर्कोसुर या मर्कोसुल दक्षिण अमेरिकी देशों का एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है जिसके सदस्य अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे और पैराग्वे हैं। संगठन की स्थापना सन 1991 में एसन्शियन संधि के द्वारा की गयी थी, जिसे 1994 में संशोधित कर ऑरो प्रेटो संधि का रूप दिया गया।
- इस संगठन का **उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार के अतिरिक्त लोगों, माल और मुद्रा का मुक्त प्रवाह** है। संगठन का **मुख्यालय उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो** में है और इसकी आधिकरिक भाषायें पुर्तगाली, स्पेनी और गुआरानी हैं।
- वर्तमान में चिली, बोलीविया, कोलम्बिया, ईक्वाडोर और पेरू को सहयोगी सदस्य का दर्जा दिया गया है।

रिसोर्ससैट -2ए रिमोट सेंसिंग उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

- अपनी 38वीं उड़ान (पीएसएलवी-सी36) में, इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 1, 235 किलो भार के रिसोर्ससैट -2ए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रेक्षपण किया। यह पीएसएलवी का लगातार 37वां सफल मिशन है।
- रिसोर्ससैट के तीन पेलोड हैं। इनमें दो लीनियर इमेर्जिनग सेल्फ स्कैनर कैमरा हैं। एक कैमरा उच्च रिजॉलूशन वाला है जो दृश्य तथा निकट अवरक्त क्षेत्र स्पेक्ट्रम में तस्वीरें लेने के काम आयेगा जबकि दूसरा कैमरा मध्यम रिजॉलूशन वाला है और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड बैंड में तस्वीरें लेगा।
- तीसरा पेलोड एडवांस वाइड फिल्ड सेंसर कैमरा है जो दृश्य एवं निकट अवरक्त क्षेत्र में तीर बैंडों में और शॉर्टवेव इंफ्रारेड में एक बैंड में काम करेगा। इसमें दो रिकॉर्डर हैं जिनकी क्षमता दो-दो सौ गीगाबाइट डाटा स्टोर करने की है। इस उपग्रह की पूर्वानुमानित आयु पाँच साल है।
- 2003 में रिसोर्ससेट-1 लॉन्च किया गया था। वहीं 2011 में रिसोर्ससेट-2 लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत की यह बड़ी सफलता है। 1963 में केरल स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग से पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया था। इसके बाद से इसरो अबतक अंतरिक्ष कार्यक्रम में सफलता के झंडे गाड़ चुका है। 2014 में भारतीय मंगलयान का पहले ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंच जाना इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।

रिसोर्ससैट -2ए के लाभ

- यह रिसोर्ससैट-1 और 2 की कड़ी का सैटलाइट है। यह सैटलाइट भारत के जमीनी संसाधनों के बारे में जानकारी देगा। मसलन यह भारत की वन संपदा और जल संसाधनों के बारे में जानकारी देगा। इससे यह जानने में भी मदद मिल सकती है कि देश के किन इलाकों में कौन से मिनरल हैं।
- रिसोर्ससैट -2ए द्वारा भेजा गया डेटा फसल क्षेत्र और फसल उत्पादन अनुमान, सूखे की निगरानी, मिट्टी मानचित्रण, फसल प्रणाली विश्लेषण और कृषि परामर्श से संबंधित कृषि अनुप्रयोगों में उपयोगी हो जाएगा।

डिजिटल भुगतान प्रणाली पर मुख्यमंत्रियों की समिति गठित:

- नीति आयोग की ओर से डिजिटल भुगतान प्रणाली देश में पारदर्शिता, वित्तीय समावेश और स्वस्थ आर्थिक तंत्र को मजबूत करने तथा आम आदमी के स्तर पर डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
- समिति के सदस्यों में ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायण सामी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस शामिल हैं।
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को भी समिति का सदस्य बनाया गया है जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत इसके सदस्य सचिव होंगे। इनके अलावा समिति में विभिन्न क्षेत्रों के पांच विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा गया है।

सिनेमाहॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गान, यानी 'जन गण मन' से जुड़े एक अहम आदेश में 30 नवम्बर 2016 को कहा कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान ज़रूर बजेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा, तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़ा होना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ध्यान रखा जाए कि किसी भी व्यावसायिक हित में राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी तरह की गतिविधि में ड्रामा क्रिएट करने के लिए भी राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं होगा, तथा राष्ट्रीय गान को वैरायटी सॉन्ग के तौर पर भी नहीं गाया जाएगा।
- दरअसल, श्याम नारायण चौकसे की याचिका में कहा गया था कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए राष्ट्रीय गान के चलन पर रोक लगाई जानी चाहिए, और एंटरटेनमेंट शो में ड्रामा क्रिएट करने के लिए राष्ट्रीय गान को इस्तेमाल न किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि एक बार शुरू होने पर राष्ट्रीय गान को अंत तक गाया जाना चाहिए, और बीच में बंद नहीं किया जाना चाहिए।

वाटर वेव लेजर:

- वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला वाटर वेव लेजर विकसित करने में सफलता हासिल की है। यह लेजर प्रकाश और पानी के माध्यम से लेजर किरणें छोड़ता है। कोशिका विज्ञान को समझने और नई दवाओं के प्रयोग में यह सहायक हो सकता है।
- यह लेजर टेक्नियन इजरायल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। यह नैनो स्तर पर होने वाले शोध में वैज्ञानिकों के लिए नए रास्ते खोलेगा। नैनो तकनीक में मनुष्य के बाल से भी छोटे पैमाने पर शोध को अंजाम दिया जाता है।
- वाटर वेव लेजर की यह तकनीक दो क्षेत्रों नॉन लीनियर ऑप्टिक और वाटर वेव को जोड़ने वाली है। अब से पहले इन दोनों क्षेत्रों को पूरी तरह अलग माना जाता रहा है। शोधकर्ता ताल कारमन ने कहा कि फ्रीक्वेंसी में अंतर के कारण अब तक पानी और प्रकाश को मिलाकर लेजर का प्रयोग नहीं किया गया है। फ्रीक्वेंसी का अंतर लेजर विकिरण के लिए जरूरी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होने देता। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित खास उपकरण फ्रीक्वेंसी के इस अंतर के कारण ऊर्जा में होने वाली कमी को संतुलित करता है।

वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत :

• मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 1 दिसम्बर 2016 को देश के 160 से ज्यादा केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंनेकर ने 'वित्तीय साक्षरता अभियान' की शुरुआत करते हुए पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण द्वारा मोबाइल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लेनदेन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई।

• तकनीक की खूबियों का जिक्र करते हुए जावडेकर ने कहा कि वर्तमान युग तकनीक का है जिसमें आज हम एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े हुए हैं।

एशिया के सबसे लम्बे साईकिल राजमार्ग का उद्घाटन:

• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा के मध्य, भारत के पहले और एशिया के सबसे लम्बे साइकिल राजमार्ग (bicycle highway) का उद्घाटन किया।
• इसके साथ ही भारत भर के एवं पांच देशों के 90 साईकिल सवारों की एक रैली का उद्घाटन इटावा में लायन सफारी से किया गया।

ओपेक देश कच्चा तेल उत्पादन में कटौती पर राजी:

तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य देशों ने उत्पादन में कटौती पर विचार-विमर्श किया और कटौती पर राजी हुए। इससे प्रमुख बाजारों में तेल कीमतों मेंे तेजी देखने को मिली। ओपेक आठ साल में पहली बार उत्पादन में कटौती पर विचार कर रहा है और उस पर लगभग सहमति बन गयी है।

मुख्य बिंदु

- 2008 के बाद पहली बार ओपेक कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करेगा। ओपेक में क्रूड उत्पादन में 12 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती पर सहमति बनी है। ओपेक देशों के लिए कच्चे तेल उत्पादन की नयी सीमा करीब 3.25 लाख करोड़ बैरल तय की गयी है।
- सऊदी अरब के लिए क्रूड उत्पादन की सीमा कम कर एक करोड़ बैरल कर दी गयी है, वहीं ईरान के लिए इसे 37 लाख 97 हजार बैरल किया गया है। जबकि इंडोनेशिया ओपेक से बाहर हो गया है। इस कारण उसके हिस्से का कोटा दूसरे देशों में बांटा गया है।

डॉ कर्ण सिंह ऑरोविले फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में पुनः नामित

- प्रख्यात विद्वान, राज्यसभा सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. कर्ण सिंह को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त निकाय ऑरोविले फाउंडेशन के संचालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया गया है। डॉ सिंह को चार साल के कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया गया है।
- ओरोविल दक्षिण भारत स्थित पुडुचेरी के पास तमिलनाडु राज्य के विलुप्पुरम जिले में एक "प्रायोगिक" नगरी है। इसकी स्थापना 1968 में मीरा रिचर्ड (भारत में निश्चित तौर पर बस जाने के बाद उन्हें "मां" कहा जाने लगा) ने की तथा इसकी रूपरेखा वास्तुकार रोजर ऐंगर ने तैयार की थी।
- ओरोविल भारत के संविधान के एक अधिनियम के माध्यम से ओरोविल फाउन्डेशन द्वारा शासित है। अतः ओरोविल फाउंडेशन के सचिव किसी व्यक्ति विशेष की ओरोविल सदस्यता की पुष्टि या उसे खारिज करने के प्रभारी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लिए प्रदूषण कोड को मंजूरी दी

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्लीा और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रदूषण कोड को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने केंद्र से प्रदूषण कोड अधिसूचित करने को कहा है। अब केंद्र सरकार इस ग्रेड प्रणाली को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी और इपीसीए- एनवायमेंट पॉल्यूरशन कंट्रोल अथॉरिटी इस बात की निगरानी करेगी कि दिल्ली सरकार, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे कैसे लागू किया।
- इस प्रदूषण कोड के तहत दिल्लील एनसीआर में प्रदूषण की चार कैटेगरी – खराब, बहुत खराब, गंभीर और काफी गंभीर तय की गई हैं। ग्रेगेड सिस्टम को चार भागों में बांटा गया है:

- Severe or Emergency: इस नए ग्रेडिंग सिस्ट म के अनुसार अगर जब हवा में पीएम 2.5 का स्तेर 300 माइक्रोग्राम प्रति क्यू:बिक मीटर या पीएम 10 की मात्रा अगर 500 माइक्रोग्राम प्रति क्यू बिक मीटर को पार कर जाए और ये स्थिति 48 घंटे या उससे ज्याकदा के लिए बनी रहे।
- Severe: इस कैटेगरी के तहत PM 2.5 की मात्रा 250 माइक्रोग्राम प्रति क्यूरबिक मीटर से ऊपर या PM10 अगर 430 माइक्रोग्राम प्रति क्यूउबिक मीटर से ऊपर हो।
- Very poor – जब पीएम 2.5 121-250 के बीच में रहे और पीएम 10 351-430 के बीच में हो।
- Moderate to poor category: अगर पीएम 2.5 का स्त र 91-120 के बीच हो या पीएम 10 का स्तमर 251-350 के बीच हो।

भारत की पहली महिला राजनीतिक पार्टी का गठन

- विभिन्न कार्यक्षेत्र से संबंध रखने वाली महिलाओं ने एकजुट होकर समाज में एकता का संदेश देने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। ऑल इंडिया वूमन युनाइटेड पार्टी (एआइडब्ल्यूयूपी) का गठन महिलाओं की राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए किया गया है।
- यह पार्टी अपनी तरह की पहली पार्टी है जिसकी सभी सदस्य महिला हैं। पार्टी अध्यक्ष नसीम बानो खान ने बताया कि उनकी पार्टी समानता के सिद्धातों पर भारत में एक लोकतात्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राज्य के निर्माण के लिए समर्पित है और महिलाओं के लिए सम्मान के लिए प्रयासरत रहेगी। अखिल-महिलाओं की पार्टी होने के नाते, हम महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- वे आगामी पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों और अन्य सभी राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पंजाब के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को बहुत जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा और वे बहुत जल्द ही मीडिया के साथ इस सूची को साझा करने जा रहे हैं।

बिजली का उपयोग करते हुए परमाणु ईंधन के उत्पादन हेतु सस्ता तरीका विकसित

- रूस के वैज्ञानिकों ने बिजली का उपयोग करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले परमाणु ईंधन के उत्पादन के लिए एक नया अनूठा, कम लागत वाला तरीका विकसित किया है।
- यह एक ऐसा नया तरीका है जोकि पाउडर धातु का आधार बनाता है और इसमें दवाब में इलेक्ट्रिक पल्स सिंटरिंग शामिल हैं।

सिमसेपे प्लेटफार्म

- यस बैंक ने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून के साथ मिलकर सिमसेपे प्ले टफार्म लॉन्च किया है। इसमें इंटरनेट कनेक्श्न की जरूरत नहीं होगी बल्कि यह एसएमएस पर आधारित होगा।
- यह ताईसिस टेक्नोलॉजी की सिम स्लीोव टेक्नोमलॉजी पर बेस्डक है। इस तकनीक का उपयोग चीन और केन्या जैसे देशों में पहले से ही किया जा रहा है। इस सेवा में आपके खाते में रजिस्टलर्ड नंबर से कॉल या मैसेज करने होंगे। इसके लिए बैंक आपको प्रत्योक ट्रांजैक्श न के लिए अलग-अलग कोड प्रोवाइड कराएगा। इसी आधार पर आप ट्रांजैक्शपन कर सकते हैं।

‘कोंकण 16’

- भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘कोंकण 16’ का 2016 संस्करण 05 से 16 दिसम्बर 2016 तक मुंबई और गोवा में किया जाएगा। इस अभ्यास का नाम भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। यह 2004 में स्थापित किया गया था।

- यह अभ्यास मुंबई और गोवा में दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण (दिसम्बर 05 से 09) मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दोनों नौसेनाएं मिलकर कमान योजना अभ्यास करेंगी। दूसरा चरण (दिसम्बर 12 – 16) गोवा में आयोजित किया जाएगा, जो एक जीवंत अभ्यास होगा, जिसमें मरीन कमांडो (मार्कोस) और रॉयल मरीन के बीच बातचीत होगी।

'लांचपैड'

- अमेज़न ने अपने वैश्विक स्टार्टअप प्रोग्राम 'लांचपैड' को भारत में शुरू किया। इस ऑनलाइन पोर्टल की विशेषता, इस पर विभिन्न स्टार्टअप्स के 400 उत्पादों का मौजूद होना है जिसमें 25 भारतीय स्टार्टअप भी हैं।
- इस कार्यक्रम से भारतीय स्टार्टअप को अपने उत्पादों को विदेशों में बेचने में मदद मिलेगी। 2015 में शुरू हुआ, अमेज़न लांचपैड अब सात क्षेत्रों में उपलब्ध है।
- अमेज़न ने भारत में 'लांचपैड' का शुभारम्भ औद्योगिक निति एवं संवर्धन विभाग के स्टार्ट अप इंडिया पहल, नैसकॉम और इंडियन एंजेल नेटवर्क के साथ मिलकर किया है।

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के इको-सेंसिटिव जोन पर अंतिम अधिसूचना जारी

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने 5 दिसम्बर 2016 को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के आसपास के 4 किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित कर दिया है।
- शहर की सीमा के भीतर स्थित जंगल के आसपास के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन घोषित करने के पीछे यह उद्देश्य है कि राष्ट्रीय पार्क के संरक्षण के लिए एक बफर क्षेत्र बनाया जा सके।

आरबीआई ने मौद्रिक नीति जारी की

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल ने 7 दिसम्बर 2016 को मौद्रिक समीक्षा पेश की। रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर को 6.25% पर अपरिवर्तित रखा है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में सभी 6 सदस्यों ने दरों में यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में मत दिया। नोटबंदी के बाद यह RBI की यह पहली मौद्रिक समीक्षा है।
- नोटबंदी से प्रभावित माहौल में केन्द्रीय बैंक ने हालांकि चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक वृद्धि का अनुमान पहले के 7.6% से घटाकर 7.1% कर दिया। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में महंगाई दर के 5% रहने का अनुमान लगाया है।
- हालांकि, इसमें वृद्धि का जोखिम भी बताया गया है फिर भी यह अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा से कम रहेगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग के तहत आवास भत्ते के पूरे प्रभाव का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है, इसके क्रियान्वयन के बाद ही इसका पता चल पायेगा इसलिये महंगाई दर में इसके असर को शामिल नहीं किया गया है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने विंटर फॉग एक्सपेरीमेंट (WIFEX 2016-17) शुरू किया

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने देश के उत्तरी भागों में कोहरे की विस्तारित अवधि की उपस्थिति का अध्ययन करने के लिए शीतकालीन कोहरा प्रयोग या विंटर फॉग एक्सपेरीमेंट (WIFEX 2016-17) शुरू किया है।
- यह कोहरे के विभिन्न भौतिक और रासायनिक लक्षणों को गहनता से मापने का तरीका है तथा यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए), दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

राज्यसभा में नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 पारित

14 दिसम्बर 2016 को राज्यसभा में नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 (Right of Persons with Disabilities Bill, 2014) 119 संशोधनों के साथ सर्वसम्मति से पारित किया गया ।
नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुरूप है। विधेयक में दिव्यांग जनों के साथ भेदभाव करने को दंडनीय बनाया गया है।
नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 ,नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 1995 की जगह लेगा |

बिल के मुख्य प्रावधान:

- 1995 के कानून में दृष्टिहीन, कम दिखाई देना, कुष्ठ पीड़ित, बधिर, चलने में असमर्थ, मानसिक रूप से अस्वस्थ और विक्षिप्त 7 वर्गीकरण थे। 2014 में प्रस्तावित बिल में इन्हें बढ़ाकर 21 किया गया। इनमें सेरिब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आटिज्म और थैलेसीमिया शामिल थे। संशोधन समिति की सिफारिश के बाद एसिड अटैक पीड़िता और पार्किंसन पीड़ितों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है।
- बिल में दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण प्रदान किया गया है। पूर्व में आरक्षण तीन प्रतिशत था। दिव्यांगों को देशव्यापी परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा जो पूरे देश में मान्य होगा। केंद्र सरकार ने केरल में दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की है।
- अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने हेतु नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 में दिव्यांगों की श्रेणी में वृद्धि की गयी है. आंकड़ों के अनुसार दिव्यांगों की जनसंख्या 2 करोड़ 59 लाख है।
- दिव्यांगों से भेदभाव पर नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 में छह महीने से दो साल तक की सजा और 10 हजार से दो लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

भारत और किर्गिस्तान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और सांस्कृतिक, सूचना एवं पर्यटन मंत्रालय व किर्गिज़स्तान गणराज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य है –

- पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए।
- पर्यटन से संबंधित जानकारी और डेटा का आदान-प्रदान करने के लिए।
- होटल और टूर ऑपरेटरों सहित पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए।
- मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए विनिमय कार्यक्रम स्थापित करना।
- पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए।
- संवर्धन, विपणन, गंतव्य विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए।
- सुरक्षित , सम्मानजनक और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए।

इस एमओयू का लाभ

दोनों देशों में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने से दोनों पक्षों के आर्थिक विकास को एक दिशा मिलेगी |

ग्रामीण विकास मंत्रालय और खाद्य व कृषि संगठन (एफएओ) के बीच समझौते को मंजूरी

कैबिनेट के बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और खाद्य व कृषि संगठन (एफएओ) के बीच समझौते को मंजूरी दी गई। इससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार होने के साथ आपस की जानकारी भी साझा की जा सकेगी।

मुख्य बिंदु

- इससे दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के अनुभवों को साझा करने में मदद मिलेगी।
- यह ग्रामीण आबादी की आजीविका को मजबूत करने के साथ ही प्रमुख फसलों, कृषि औद्योगिक उत्पादों, रोजगार विविधीकरण, कौशल विकास और विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए समावेशी व सतत मूल्य श्रृंखला विकसित करेगा।

मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2016

सरकार ने मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, 2016 को मंजूरी दे दी। सरकार ने फैसले लेने में पोर्ट्स को पूरी ऑटोनॉमी देने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे वे पूरी क्षमता और पेशेवर तरीके से काम कर सकें। यह बिल मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की जगह लेगा।

मुख्य बिंदु

- इस बिल के पारित होने से बड़े पोर्ट्स ज्यादा क्षमता से काम कर सकेंगे और उन्हें फैसले लेने के लिए पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी। साथ ही बड़े पोर्ट्स के लिए अपने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करना आसान हो जाएगा।
- यह बिल पुराने मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 की तुलना में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें अप्रचलित सेक्शंस को खत्म करके इनकी संख्या 134 से घटाकर 65 कर दी गई है।

हरियाणा में महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल शुरू

हरियाणा में 14 दिसम्बर 2016 को महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल की शुरुआत की गयी। करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में इस पहल को शुरू करने के साथ ही हरियाणा इस योजना को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है।

मुख्य बिंदु

- मूल रूप से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा परिकल्पित, महिला पुलिस स्वयंसेवी केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ एक संयुक्त पहल है।
- हरियाणा ने आज 1000 महिला पुलिस स्वयंसेवी के पहले बैच को शामिल किया।
- इन स्वयंसेवी को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के लिए राज्य के पुलिस अधिकारियों द्वारा पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।

भारत ने IBRD के साथ समझौता किया

- एमएसएमई की परियोजना 'ऊर्जा दक्षता के लिए प्रोग्रामेटिक फ्रेमवर्क' पर अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) के साथ 5.19 मिलियन के एक अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
- केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव राज कुमार और IBRD की ओर से विश्व बैंक के निदेशक (भारत) जुनैद अली अहमद ने इस समझौते पर किये. आईबीआरडी वैश्विक पर्यावरण सुविधा के एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है.
- आईबीआरडी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है और मुख्य रूप से मध्यम आय वाले देशों को ऋण और अन्य सहायता प्रदान करती है।

आवास एवं शहरी विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन और शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने 'आवास एवं शहरी विकास संबंधी एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन' का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र का वैश्विक शहरी आबादी में 55 फीसदी हिस्सा है।
- 1 अरब से भी अधिक लोग झुग्गियों में रहते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूरी दुनिया में होने वाली मौतों में 75 फीसदी हिस्सा इसी क्षेत्र का है। श्री नायडू ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि इस क्षेत्र में हो रहे त्वरित शहरीकरण से उपजी चुनौतियों का सामना करने के लिए वे एकजुट होकर प्रयास करें।
- समावेशी, सुरक्षित, लचीले एवं टिकाऊ शहरों के निर्माण के जरिये न्यायसंगत शहरी विकास के सपने को साकार करने हेतु अगले 20 वर्षों के लिए क्रियान्वयन योजना विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।

जनजातीय आजीविका के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का होगा शुभारंभ

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यूएनडीपी और राष्ट्रीय जनजातीय वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के साथ भागीदारी से जनजातियों के आजीविका से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए भुवनेश्वर में राष्ट्रीय संसाधन केंद्र 'वनजीवन' का शुभारंभ करेंगे।

वनजीवन

- वनजीवन पहले चरण में कम जनजातीय लोगों में कम एचडीआई वाले चुनिंदा छह राज्यों में आजीविका संबंधी समस्याओं की पहचान करने वाले कार्यक्रम के तौर पर होगा। इसमें असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना शामिल हैं।
- दूसरे चरण में इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में लागू किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम में कौशल के मौजूदा स्तर को ध्यान में रखते हुए स्थानीय संसाधनों की पहचान पर जोर रहेगा।
- इस कार्यक्रम से उक्त उद्देश्य के लिए कई सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत कोष का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा।
- राष्ट्रीय संसाधन केंद्र आजीविका मानचित्रण, कौशल अंतर विश्लेषण और नॉलेज हब के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, जहां जनजातीय उद्यमशीलता विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ आजीविका और उद्यमशीलता मॉडल उपलब्ध होंगे।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट के मुताबिक, मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में और अधिक धन की तत्काल आवश्यकता है।

मुख्य बिंदु

- 2015 में मलेरिया से 429000 लोगों की मृत्यु हुई है वहीँ 212 मिलियन नए मामले प्रकाश में आए है । इसके अलावा, 2015 में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया के मामलों की लगभग 78% सिर्फ चार देशों इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में हुई।
- मलेरिया कार्यक्रमों पर खर्च अरबों डॉलर के बावजूद भी कई लोग , उपलब्ध संसाधनों (जैसे दवाओं और मच्छरदानी ,जो मच्छरों कि इस बीमारी के प्रसार के खिलाफ रक्षा करता है), से वंचित हैं।
- निगरानी प्रणाली को मलेरिया के कुल मामलों का 20 % से भी काम मामलों का पता चल पाता है | मलेरिया के सबसे अधिक मामला अफ्रीका में है | कुल मामलो का70%, 5 वर्ष से काम उम्र के बच्चों का है |

पृष्ठभूमि

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2015 तक मलेरिया के मामलो को लगभग ०% पर लाने का लक्ष्य रखा था जिससे वह काफी पीछे छूट गया और अब 2030 तक कम से कम 90% से मलेरिया के मामलों और मौतों को कम करने के लिए नया लक्ष्य है।

केंद्र के द्वारा साइबर सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा

सरकार साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 15 साल पुराने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), अधिनियम की समीक्षा पर विचार कर रही है

मुख्य बिंदु

- आईटी सचिव अरुणा सुंदरराजन की अध्यक्षता में समिति स्थापित की गई है जो बदलते समय के साथ लाइन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेगी ।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) के अन्तर्गत एक 'डिजिटल भुगतान' डिवीजन की स्थापना की है, जो साइबर सिक्योरिटी की कैशलेस ट्रांजेक्शन पर नज़र रखेगी और उसे मज़बूती प्रदान करेगी ।
- सभी डिजिटल भुगतान एजेंसियों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ असामान्य गतिविधि होने पर cert in को रिपोर्ट करने को कहा गया है ।

'इंद्र नेवी-2016'

भारत और रूस की नौसेना 14 दिसम्बर 2016 से बंगाल की खाड़ी में अपना आठ दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया।

मुख्य बिंदु

- इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच अंतर-संचालनात्मकता को बढ़ाना है। वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास 'इंद्र नेवी' का नवां संस्करण 14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक चलेगा।

- नौसेना की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालनात्मकता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए साझा समझ और प्रक्रियाओं को विकसित करना है।
- पहली बार दोनों देशो के नौसेनाओ के मध्य सैन्य अभ्यास वर्ष 2003 में हुआ था।

अभ्यास ईकुवेरिन-2016

- 15-28 दिसंबर, 2016 के दौरान भारत और मालदीव के मध्य सातवां संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अभ्यास ईकुवेरिन' (Exercise EKU-VERIN-2016) का आयोजन कधधू लामू एटोल, मालदीव में किया जायेगा।
- यह 14 दिवसीय अभ्यास भारतीय सेना एवं मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच प्लाटून स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- जिसका आयोजन वर्ष 2009 से भारत एवं मालदीव में बारी-बारी वार्षिक आधार पर किया जाता है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य अंतः पारस्परिकता बढ़ाने के विचार से अराजकता/आतंकरोधी संचालनों पर विशेष जोर के साथ सैन्य प्रशिक्षण का संचालन करना है।
- उल्लेखनीय है कि प्लाटून की टुकड़ियों में बिहार रेजीमेंट के जवान तथा इतनी ही संख्या में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के जवान शामिल हैं।
  इस अभ्यास का पिछला संस्करण वर्ष 2015 में भारत में केरल के त्रिवेंद्रम, केरल में आयोजित किया गया था।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भारत दौड़ा

इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री जोको विडोडो 11 से 13 दिसंबर 2016 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। राष्ट्रपति जोको विडोडो की भारत यह पहली द्वपक्षीय यात्रा है।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने वार्षिक शिखर सम्मेलन की बैठकें आयोजित करने पर सहमति जताई जिसमें बहुपक्षीय कार्यक्रम भी शामिल हैं।

प्रमुख समझौते:

- खेल एवं युवा सहयोग: भारतीय युवा मामले एवं इंडोनेशिया खेल मंत्रालय के मध्य यह समझौता किया गया।
- मानकीकरण सहयोग पर समझौता ज्ञापन: भारत गणराज्य के भारतीय मानक ब्यूरो तथा इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रीय मानकीकरण एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन।
- स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर संयुक्त विज्ञप्ति: दोनों देशों द्वारा समुद्री सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसके तहत समुद्री सुरक्षा सहित, मछली पालन एवं सतत विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- आतंकवाद की समस्या से निपटने से सम्बंधित तथ्य के मामले में जारी संयुक्त बयान में आतंकवादी घोषित करने से संबंधित यूएनएससी प्रस्ताव 1267 और अन्य सम्बद्ध प्रस्तावों को लागू करने के लिए आह्वान किया गया।

रतन वाटल समिति रिपोर्ट

पूर्व वित्त सचिव रतन वाटल की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के तरीके का सुझाव दिया है |

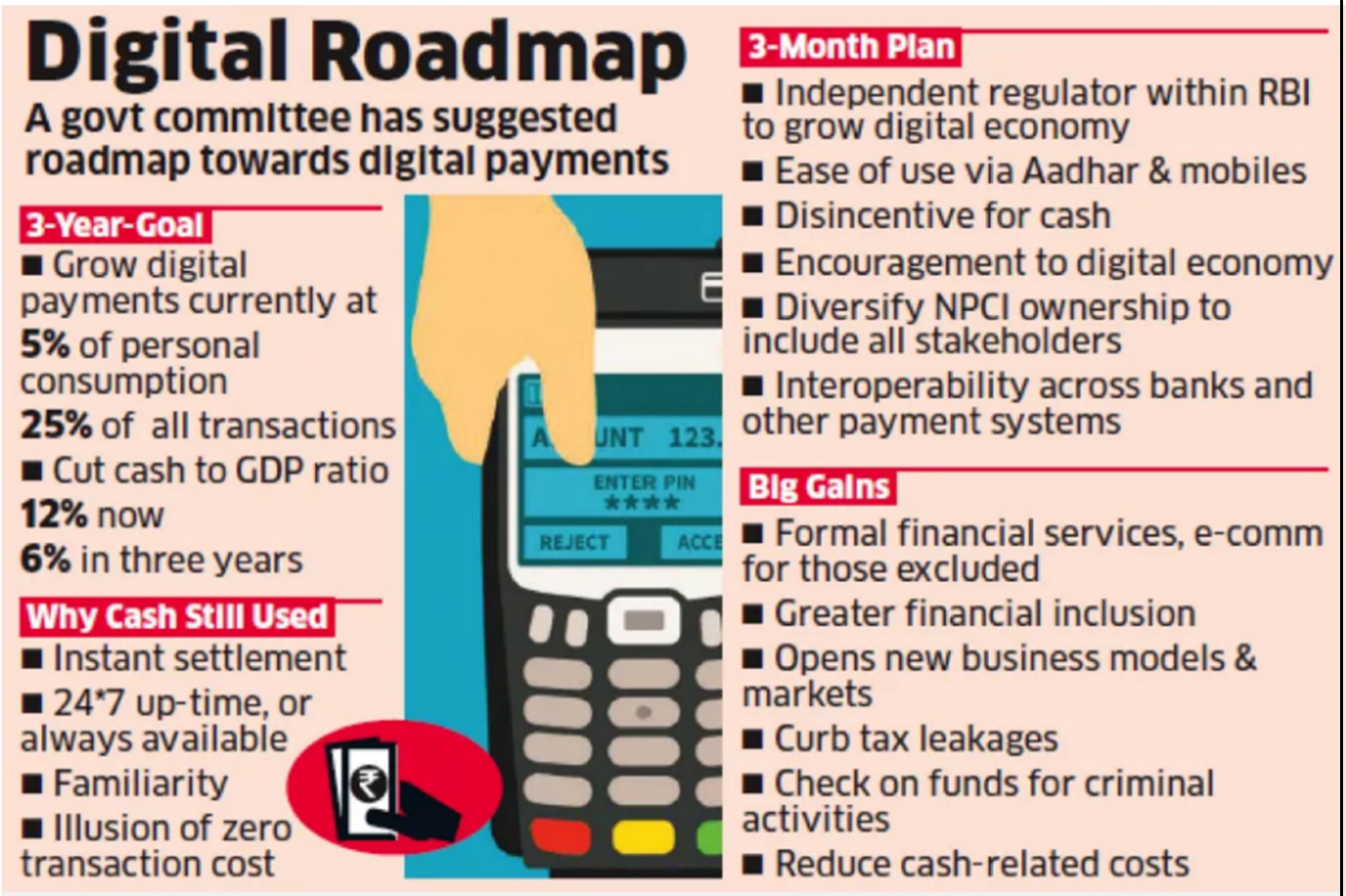

SOURCE: Times of India

पृष्ठभूमि

सरकार ने कैश लेस अर्थव्यवस्था की तरफ एक कदम उठाते हुए 8 नवम्बर से 500 और 1000 के पुराने नोट्स को बंद कर दिया है |

मुख्य सलाह

- समिति ने समग्र केंद्रीय बैंकिंग ढांचे के भीतर एक स्वतंत्र तंत्र का सुझाव दिया है।
- समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है की डिजिटल भुगतान को आसान व सरल बनाने के लिए आधार कार्ड व मोबाइल का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए |
- बैंक और गैर-बैंकों के बीच और साथ ही गैर-बैंकों के भीतर अंतर-प्रचलित भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम को अपनाया जाए
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र भुगतान नियमन बनाने की बात कही गई है जो की केंद्रीय बैंक से अलग हो |
- समिति ने सुझाव दिया है कि ,विनियमन और भुगतान के पर्यवेक्षण और निपटान प्रणाली (BPSS) के बोर्ड को भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर्गत एक स्वतंत्र वैधानिक दर्जा दिया जा सकता है और इसे भुगतान नियामक बोर्ड कहा जाएगा । BPSS वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति के रूप में कार्य करता है।

- समिति ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है और इसके अलावा प्रतिस्पर्धा और नवीनता, खुली पहुंच और अंतर, उपभोक्ता संरक्षण, प्रणालीगत जोखिम और डेटा संरक्षण पर नियमों के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश देने को कहा है।
- समिति के द्वारा एक 'DIPAYAN' निधि बनाने कि बात कही गई है जिसमे कैशलेस ट्रांजेक्शन कि वजह से बचत कि गई राशि को डिजिटल भुगतान प्रोत्साहित व विस्तार करने के लिए राज्यों, सरकारी विभागों, जिलों और पंचायतों को दिया जाएगा ।

कोलकाता-मिजोरम व्यापार मार्ग म्यांमार के माध्यम से

भारत के द्वारा बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के सितवे में बनाया गया एक गहरे पानी बंदरगाह कमीशन के लिए तैयार है।इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुविधा के लिए एक उद्घाटन समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा।

- इस समुद्री बंदरगाह के निर्माण के लिए एक एकीकृत $ 500 मिलियन के परियोजना के पहले चरण में एक लंबे समय तक भारत के द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया ।

सितवे कहां स्थित है?

सितवे दक्षिण-पश्चिमी म्यांमार में अराकान की राजधानी (जो रोहिंग्या मुसलमानों की दुर्दशा के लिए सुर्खियों में रहा है) है।यह कलादान नदी के मुहाने में स्थित है, जो उत्तर-पूर्वी भारत में मिजोरम में बहती है ।

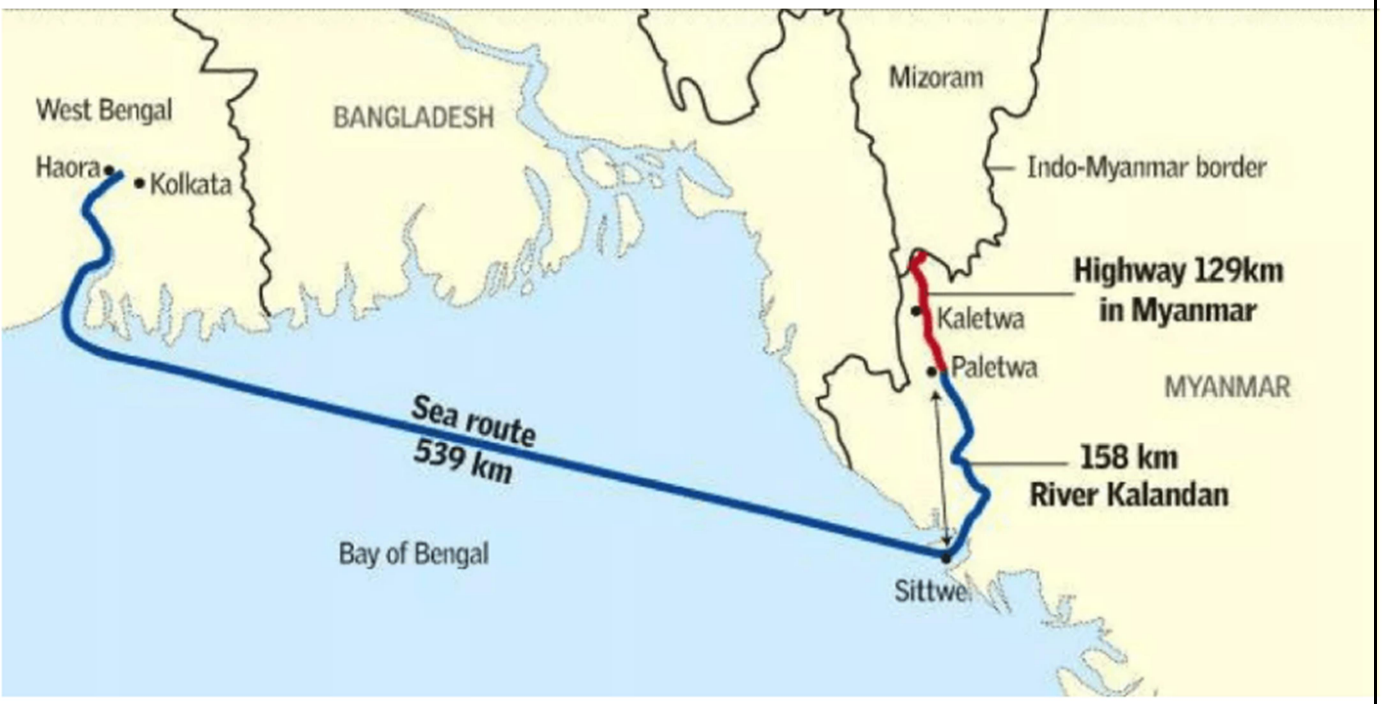

इस पोर्ट का महत्व

भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान पहुचने का आसान रास्ता मिल जाएगा और कलकत्ता से मिजोरम माल भेजने का खर्च और समय में बचत होगी |

रियल टाइम रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए डीएसटी-इंटेल का सहयोगात्मक अनुसंधान समझौता

ऑनलाइन रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग (WAQM) सिस्टम के विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और इंटेल ने संयुक्त रूप से "रियल टाइम रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सहयोगात्मक अनुसंधान" आरंभ किया है।

मुख्य बिंदु

- यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड का एक संयुक्त कार्यक्रम है।
- इस पहल का का उद्देश्य स्वायत्त नेटवर्क से एकत्रित संवेदन, संचार और लार्ज स्केल डाटा के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। यह बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में पानी और हवा की गुणवत्ता की सूक्ष्मतम जांच के लिए कम लागत, कम बिजली वाले स्वायत्त वायरलेस सेंसर नेटवर्क को विकसित और तैनात करने में मदद करेगा।
- यह कार्यक्रम भारत-अमेरिका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम (IUSSTF) के द्वारा द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश उदय में शामिल होने वाला 18वां राज्य बना

- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल होने वाले राज्यों में हिमाचल 18वां राज्य बन गया है। इस योजना में शामिल होते ही हिमाचल को 823 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में नए साल में बिजली की दरों में कमी हो सकती है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड का केंद्र सरकार के साथ उदय को लेकर करार हुआ है। इस संबंध में केंद्र सरकार व हिमाचल सरकार के मध्य समझौता हुआ। यह करार होने के साथ बिजली बोर्ड की वित्तीय हालत में भी सुधार आएगा। इसके तहत 75 फीसद देनदारियों को राज्य सरकार अपने ऊपर लेगी।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड एसईसीआई सरकारी क्षेत्र के लिए 1000 मेगावाट के छत पर लगने वाले सौर पीवी योजना को शुरू करेगा

- वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने के भारत सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में ग्रिड से जुड़े छत पर लगने वाले सौर क्षमता को विकसित करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) ने 1000 मेगावाट क्षमता की निविदा जारी किया।
- एसईसीआई द्वारा छत पर स्थापित की जाने वाली यह सबसे बडी सौर परियोजना है और छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में इससे बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- इस योजना में, छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़े ग्रिड को एमएनआरई के लिए प्रोत्साहन के रूप में आर्थिक सहायता के साथ स्थापित किया जाएगा।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत सृजित की गई ऊर्जा को ईमारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा और यदि अतिरिक्त ऊर्जा का सृजन होता है तो उसे ग्रिड के अंदर विभिन्न माध्यमों से सुरक्षित कर संबंधित राज्य के उपयोग के लिए उसका प्रबंध किया जाएगा।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड(SECI) के बारे में

- भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (सेकी)" नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 20 सितम्बर, 2011 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन और उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई थी।
- सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित यही अकेला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे मूल रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत धारा 25 (लाभ के लिए नहीं) कम्पनी के रूप में शामिल किया गया था।
- यह कम्पनी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनेक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है, जिनमें प्रमुख जेएनएनएसएम के अधीन बड़े पैमाने की ग्रिड सम्बद्ध परियोजनाओं के लिए वीजीएफ योजनाएं, सौर उद्यान योजना और ग्रिड सम्बद्ध सौर रूफटॉप योजना है और इनके साथ-साथ रक्षा योजना, कनाल-टाप योजना, भारत-पाक सीमा योजना आदि जैसी काफी अन्य विशेषीकृत योजनाएं हैं।

सरकार के द्वारा जनता से खाद्य पैकेजिंग सामग्री के रूप में समाचार पत्र के उपयोग को प्रतिबंधित करने का आग्रह

- भारत में खाद्य पैकेजिंग सामग्री के रूप में समाचार पत्रों के उपयोग पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को निर्देश दिए कि वह खाने-पीने की चीजों को पैक करने के लिए अखबार के कागज का इस्तेमाल बंद करने के लिए एक एडवाइजरी जारी करे।
- सरकार ने कहा कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य संरक्षा आयुक्त खाद्य सामग्री को पैक करने व उसे परोसने के लिए अखबारों का इस्तेमाल बंद करने को लेकर सभी संबंधित हितधारकों के बीच जागरुकता फैलाने के लिए एक व्यवस्थित अभियान शुरू करेंगे।

खाद्य पैकेजिंग सामग्री के रूप में अखबार के उपयोग को सीमित क्यों किया जा रहा है ?

- अखबार की स्याही को खाद्य पदार्थ सोख लेते हैं। अखबारों में इस्तेमाल होने वाली स्याही में कई खतरनाक रसायन होते हैं जिसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं।
- अखबार की स्याही में बहुत से बायोएक्टिव तत्व होते हैं। साथ ही इसमें नुकसानदेह रंग, पिगमेंट, एडिटिव और प्रीजर्वेटिव शामिल होते हैं। इनसे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होता है। यही नहीं, इसका कागज भी अपने आप में नुकसानदेह होता है।
- अखबारों, रीसाइकिल पेपर और रीसाइकिल कार्डबोर्ड में मैटेलिक कंटेमिनेंट्स, मिनरल आयल्स और ऐसे रसायनिक तत्व हो सकते हैं जो पाचन संबंधी समस्या से लेकर गंभीर विषाक्तता तक पैदा कर सकते हैं। साथ ही ये बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों में कैंसर से जुड़ी समस्याएं तक पैदा कर सकते हैं।

नासा का नया अंतरिक्ष यान परिक्रमा करते उपग्रहों में ईंधन भर पाएगा

- नासा ने 'रिस्टोर-एल स्पेसक्राफ्ट बस' नामक एक नए प्रकार के अंतरिक्ष यान को शामिल किया है जो पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उपग्रहों के परिक्रमा करते हुए उनमें ईंधन भरने और उनकी मरम्मत करने में सक्षम होगा।
- यह यान अंतरिक्ष के कचरे को कम करने, मौजूदा उपग्रहों के जीवन को लंबा करने और संचालन लागत को घटाने में मदद करेगा।

जिराफ विलुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में

- जिराफ को विलुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में डाला गया है। पिछले सिर्फ 30 वर्षों में जिराफ की संख्या लगभग 40 फीसदी तक कम हो गई है। वैज्ञानिकों ने इसे दुनिया की ऐसी विलुप्तप्राय प्रजातियों की आधिकारिक सूची में डाल दिया है जिन पर नजर रखने की आवश्यकता है और उन्होंने इसे 'असुरक्षित स्थिति में' बताया है।
- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) के अनुसार, वर्ष 1985 में जिराफों की संख्या 1,51,000 और 1,63,000 के बीच थी लेकिन वर्ष 2015 में इनकी संख्या घटकर 97,562 हो गई। मेक्सिको में जैव विविधता पर कल हुई बैठक में आईयूसीएन ने संकटग्रस्त प्रजातियों की अपनी 'रेड लिस्ट' में शामिल सात प्रजातियों पर संकट के स्तर कमी होने और 35 प्रजातियों के संकट के स्तर में वृद्धि होने के बारे में बताया।

इटली के नए प्रधानमंत्री :-पाओलो जेंटिलोनी

पाओलो जेंटिलोनी इटली के नए प्रधानमंत्री होंगे। सुधारवादी नेता मातियो रेंजी के जनमत संग्रह में करारी हार के बाद इस्तीफा देने के साथ जेंटिलोनी नए प्रधानमंत्री होंगे।

न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री:- बिल इंग्लिश

न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाल चुके बिल इंग्लिश देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। वह जॉन की जगह पदभार संभालेंगे। वहीं न्यूजीलैंड की नई उप प्रधानमंत्री पाउला बेनेट होंगी। जॉन की के इस्तीफे की घोषणा के एक हफ्ते बाद संसदीय कॉकस ने इंग्लिश का चुनाव किया।

संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव :-एंटोनियो गुटेरेस

- पुर्तगाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री एंटोनियो गुटेरेस ने दिसम्बर 12, 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में शपथ ग्रहण किया। दक्षिण कोरियाई बान की मून का स्थान लेने वाले एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक संकटों से निबटने के लिए इस 71 वर्षीय वैश्विक निकाय की क्षमता सुधारने के वास्ते उसमें सुधार करने, उसे विकेंद्रीकृत करने एवं लचीला बनाने का निश्चय किया।
- पुर्तगाल के 67 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस एक जनवरी को बान से संयुक्त राष्ट्र की कमान संभालेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में बान का पांच साल का दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर को पूरा होगा। गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के नौंवे महासचिव बने हैं।

"100 मिलियन के लिए 100 मिलियन" अभियान

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाल श्रम, बच्चों को गुलामी और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने दि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित "100 मिलियन के लिए 100 मिलियन अभियान" शुरू किया।
- यह 100 मिलियन वंचित बच्चों के बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए 100 मिलियन युवाओं को लामबंद करने के प्रयास में एक परिवर्तन की शुरुआत है।

45वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस

- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और केरल पुलिस संयुक्त रूप से 8 व 9 दिसंबर को कोवलम, तिरुवनंतपुरम में 45वीं अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया।
- इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न पुलिस बलों/ इकाइयों, समाजिक विज्ञानियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों को भारतीय पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का मंच प्रदान करना है।

- कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस एक भावी रोड मैप पेश करेगी ताकि पुलिस बल जनता को बेहतर सुविधा और सेवा प्रदान कर सकें।
- पहली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस पटना में 1960 में आयोजित की गई थी। उसके बाद अब तक 44 कांग्रेसों का आयोजन किया जा चुका है।

नुब्रा घाटी में प्राचीन कैम्पिंग साइट

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) द्वारा हाल ही में लद्दाख में प्राचीन कैंपिंग स्थल की खोज की गयी। यह स्थान नुब्रा घाटी में 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नुब्रा घाटी में यह खोज डॉ एस बी ओटा की अध्यक्षता में बनाई गयी टीम द्वारा की गयी। उन्होंने यह खोज उस समय एक संयोग से की जब एक स्थान पर सड़क मार्ग बाधित होने के कारण उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ा।
- शोधकर्ताओं ने इस स्थान पर चारकोल के अवशेष तथा हड्डियों के अवशेष प्राप्त किये। इन टुकड़ों एवं अवशेषों अमेरिका स्थित फ्लोरिडा बीटा एनालिटिक्स विभाग के पास भेजा गया। टेस्ट के दौरान इसकी तिथि 8500 बीसी तक पुरानी पायी गयी।

मास्टर शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

- विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) 1965 से ही मास्टर शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की एक योजना लागू कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट शिल्पकारों को मान्यता देना है।
- पुरस्कार विजेता देश के लगभग हरेक राज्यों के विभिन्न शिल्प शैलियों का प्रतिनिधित्व करते है |
- पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए नकद एक ताम्रपत्र व प्रमाण पत्र दिए जाते है |
- 1965 से 2014 तक कुल 1193 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए है जिसमे से 189 पुरस्कार महिलाओं को दिए गए है

भारतीय संविधान के दायरे से बाहर नहीं है जम्मू-कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारतीय संविधान के दायरे के बाहर नहीं है और उसे भारत के संविधान के बाहर कोई संप्रभुता हासिल नहीं है। कोर्ट ने जम्मू एड कश्मीर हाई कोर्ट की राय को दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी की।
- पीठ ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के इस फैसले को दरकिनार कर दिया कि राज्य विधानमंडल से बने कानूनों पर असर डालने वाला संसद का कोई कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता।
- जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा था कि कश्मीर संप्रभु राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के बाहर जम्मू-कश्मीर को कोई भी शक्ति नहीं दी जा सकती है।
- शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला ही गलत अंत से प्रारंभ होता है अतएव वह गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच जाता है। यह कहता है कि जम्मू-कश्मीर के संविधान में अनुच्छेद पांच के सदंर्भ में राज्य को अपने स्थायी नागरिकों की अचल संपत्तियों के संदर्भ में उनके अधिकारों से जुड़े कानूनों को बनाने का पूर्ण संप्रभु अधिकार है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह साफ है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के पास भारत के संविधान और उसके अपने संविधान के दायरे के बाहर कोई संप्रभुता नहीं मिली हुई है। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों पर पहले देश का संविधान लागू होता है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर का संविधान भी लागू होता है।
- शीर्ष अदालत ने वित्तीय आस्तियां प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को संसद की विधायी क्षमता के अंतर्गत आने का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें जम्मू-कश्मीर में लागू किया जा सकता है।

- पीठ ने कहा कि हम यह भी कह सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक हैं और कोई दोहरी नागरिकता नहीं है जैसा कि दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में कुछ अन्य संघीय संविधानों में विचार किया गया है।
- शीर्ष अदालत का फैसला उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध भारतीय स्टेट बैंक की अपील पर आया है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि वित्तीय आस्तियां प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम का जम्मू कश्मीर के संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1920 से टकराव होगा।
- एसएआरएफएईएसआई एक ऐसा कानून है कि जो बैंकों को कर्जदारों की प्रतिभूत संपित्त को कब्जे में लेने एवं उन्हें बेच देने के लिए अदालती प्रक्रिया के बाहर अपने प्रतिभूति हितों को लागू करने का अधिकार देता है। शीर्ष अदालत ने 61 पन्नों के अपने फैसले में यह भी कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि उच्च न्यायालय के फैसले के कई हिस्से जम्मू कश्मीर की पूर्ण संप्रभु शक्ति का उल्लेख करते हैं।
- न्यायालय ने कहा, "यहां इस बात को दोहराना आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर का संविधान, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा ने तैयार किया था, स्पष्ट घोषणा करता है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा तथा यह प्रावधान संशोधन के दायरे के बाहर है।"

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना:

ब्लैकमनी पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इस योजना के तहत कालेधन को 50 फीसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है। यह योजना 31 मार्च 2017 तक चलेगी।

प्रमुख तथ्य:

- यह योजना 17 दिसम्बर 2016 को शुरू हो गई है। यह योजना 31 मार्च 2017 को बंद होगी। इसके तहत हुए खुलासे पर 50 फीसदी टैक्स और जुर्माना लगेगा। बाकी की 25 फीसदी रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
- अगर आपकी अघोषित आय 10 लाख निकलती है तो आपको 10 लाख का 30 फीसदी यानी 3 लाख रुपए आमदनी टैक्स देना होगा। उसके अलावा 10 फीसदी यानी 1 लाख रुपए आपको इनकम पर पैनल्टी के रूप में देना होगा और 30 फीसदी का 33 फीसदी यानी 3 लाख का 99 हजार रुपये आपको सरचार्ज देना होगा।इसके हिसाब से आपको 10 लाख पर 50 फीसदी जुर्माना यानी 4,99,000 रुपए टैक्स के रूप में चुकाना होगा।
- अघोषित आय के बारे में बताने वालों के नामों का खुलासा नहीं होगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2017 के बाद जो पकड़े जाएंगे उनकी खैर नहीं है। टैक्सचोरी पर पूरी आय जब्त हो सकती है और करीब 77 फीसदी न्यूनतम टैक्स चुकाना होगा।
- नए इनकम डिसक्लोजर स्कीम के अंतर्गत आप नई ईमेल आईडी blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर जानकारी दे सकते हैं। इस आईडी के जरिए कालेधन का खुलासा करने वाले लोगों के नामों को गुप्त रखा जाएगा।
- अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपना पैसा डिक्लेयर करता है तो यह पैसा उसकी इनकम में शामिल नहीं माना जाएगा। यानी की अगर किसी ने अपना पैसा इस स्कीम के तहत डिक्लेयर कर दिया तो इसके बाद उस पैसे पर किसी और स्कीम के तहत सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
- जुर्माने से जो राशि आएगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिना हिसाब का पैसा डिक्लेयर करते हुए अगर कोई व्यक्ति जानकारी छिपाता है या गलत जानकारी देता है तो उसका डिक्लेयरेशन रद्द हो जाएगा और स्कीम के तहत चुकाया गया टैक्स और पेनल्टी भी वापस नहीं मिलेगी।
- यह योजना हाल में समाप्त हुई आय घोषणा योजना 2016 से भिन्न है जिसमें कालेधन का खुलासा पहले किया जाता था तथा कर का भुगतान बाद में।

वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2016-17

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation – ILO) ने वैश्विक मजदूरी पर अपनी नवीन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012 के बाद से वैश्विक वेतन वृद्धि दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जो वर्ष 2012 के 2.5 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2015 में 1.7 प्रतिशत तक आ गई।वस्तुतः यह विगत चार वर्षों में अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है।
- इस डाटा के मुताबिक भारत में पुरुष पुरुष मजदूरों के मुकाबले महिला मजदूरों को 33 फीसदी कम वेतन मिलता है। इन आंकड़ों से साफ है कि दुनिया के देशों के मुकाबले भारत में पुरुष मजदूरों के मुकाबले महिला मजदूरों काफी कम वेतन मिलता है।
- रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों महिलाओं को 63 फीसदी कम वेतन मिला है लेकिन इनमें 15 फीसदी ज्यादा वेतन है। इस तथ्य को छोड़ दें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक हाल में जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की है उनमें पुरषों के मुकाबले ज्यादा महिला डॉक्टर और शिक्षक हैं।
- इसके साथ-साथ नॉन टेक्निकल फील्ड में भी पुरुषों के मुकाबले सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं ही हैं। रसियन फेडरेशन से तुलना की जाए तो यहां महिला मजदूरों को 40 फीसदी ज्यादा वेतन दिया जाता है। महिला मजदूरों में वेतन का ये अंतर निचले स्तर तक है, हालांकि मनरेगा के तहत कि महिला और पुरुष मजदूरों को वेतन का अंतर करने की कोशिश की गई थी।
- भारत में वेतन असमानता अकेले लिंग अनुपात की वजह नहीं है। देश के आधे से ज्यादा मजदूर जिन्हें कम वेतन मिलता है उनका आंकड़ा करीब 17.1 फीसदी है। वहीं टॉप 10 फीसदी मजदूरों को 42.7 फीसदी मजदूरी मिलती है। केवल दक्षिण अफ्रीका में ये ज्यादा असमान है। इन आंकड़ों के मुताबिक हालात इतने खराब नहीं हुए हैं। भारत में बीते दशक में औसत मजदूरी 60 फीसदी पहुंच गई है। ये आंकड़ा चीन से दोगुना है।
- गौरतलब है कि आईएलओ द्वारा यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों में प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट से निकलने वाला एक महत्त्वपूर्ण संकेत यह भी है कि जी-20 के वैसे देश जो 2008-09 की आर्थिक मंदी में बेहतर स्थिति में थे, अब वेतन वृद्धि दर में गिरावट की मार झेल रहे हैं।

निष्कर्ष:

न्यूनतम मज़दूरी और सामूहिक संविदा के द्वारा अत्यधिक पारिश्रमिक असमानताओं को कम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण सुधार किये जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में पारिश्रमिक का नियमन करना चाहिये, साथ ही, दीर्घकालिक उद्यमों की उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास भी किये जाने चाहियें। इन सबके आलावा, उन कारणों की पहचान करते हुए समाधान के उपाय निकाले जाने चाहियें जो महिलाओं और पुरुषों के बीच पारिश्रमिक-असमानता को बढ़ावा देते हैं।

भारत में जंगल की आग में चिंताजनक वृद्धि :

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार,भारत भर में जंगल की आग में चिंताजनक वृद्धि हुई है। वर्ष 2016 में जंगलों में लगने वाली आग के 24, 817 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि 2015 में यह आंकड़े 15,937 दर्ज किए गए थे। पिछले एक वर्ष में जंगलों में लगने वाली आग में 55 फीसदी की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- रिपोर्ट मुख्य रूप से हिमालय के जंगलों में आग की रोकथाम पर केंद्रित है जोकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर भर में फैली हुई है।
- यद्यपि 2015 को सूखे का वर्ष माना गया फिर भी जंगल की आग में बढ़ोत्तरी हुई। लेकिन इस बीच जंगल की आग की बारंबारता में लगभग 16% की गिरावट आई है।

- तीन केंद्रीय राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जंगल की आग में एक तिहाई का योगदान करते हैं।
- मध्य प्रदेश में जंगल की आग में लगभग दस गुना वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें 2015 में सिर्फ 294 मामलों से बढ़कर 2016 में 2,600 से अधिक मामले दर्ज किये।
- हिमाचल और उत्तराखंड में,17,502 एकड़ जमीन को जंगल की आग के कारण 2016 में तबाह होना पड़ा जोकि पिछले वर्ष से 171 फ़ीसदी अधिक है।
- ज्यादातर फ्रंट लाइन वन कर्मचारियों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े थे, जबकि अग्निशमन उपकरण कई मामलों में अल्पविकसित है।

प्रमुख सिफारशें:

- जंगल की आग के प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए।
- पाइन रिज़र्व फॉरेस्ट्स को "ब्रॉड-लीफ़" पत्तियों वाले पौधों के साथ बदल देना चाहिए।
- चीड़ पाइन नीडल्स को सड़क के किनारे से साफ़ करने के लिए व्यापक मशीनों की खरीद की जाए।

पृष्ठभूमि:

समिति का गठन राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी की अध्यक्षता में वर्ष 2016 में उत्तराखण्ड की भीषण आग के बाद किया गया था।

पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2007 में संशोधन

- सरकार ने पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (NEIIP), 2007 में संशोधन किया है, और यह तय किया है कि औद्योगिक इकाइयों के लिए सभी सब्सिडियों का वितरण डीबीटी तंत्र के माध्यम से होगा।
- सरकार ने फैसला किया है कि सभी औद्योगिक इकाइयों को अब सब्सिडी का वितरण मुख्य लेखा नियंत्रक (उद्योग) द्वारा देय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए इकाइयों को आवश्यक बैंक विवरण प्रदान करके ई-भुगतान पोर्टल पर पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।
- विनिर्माण क्षेत्र में सक्रिय नई औद्योगिक इकाइयों / मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को 5 करोड़ रुपये प्रति औद्योगिक इकाई और सेवा क्षेत्र में सक्रिय इकाइयों को प्रति औद्योगिक इकाई 3 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
- 1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश पर सब्सिडी के अनुदान के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति बनायी जाएगी। समिति की अध्यक्षता सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा की जायेगी।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग:

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक विभाग है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और 2000 में इसकी पुनर्स्थापना की गई। तब इसे औद्योगिक विकास विभाग के संग विलय कर दिया गया था।

ई-बिज़ पोर्टल:

- ईबिज़ भारत सरकार की ऐसी सुविधा है जहाँ एक ही जगह पर सरकार से व्यवसाय (जी 2 बी) सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक खाता बनाने की जरूरत है।

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की इस पोर्टल की मदद सेउपयोगकर्ता अपने सभी लाइसेंस, मंजूरी, पंजीकरण और नियामक फाइलिंग के लिए आवेदन और प्रबंधन कर सकते हैं। व्यवसाय शुरू करने और इसे चलाने से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

केंद्र का राज्यों/ केंद्र शाषित प्रदेशों को निर्देश: राष्ट्रीय गान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवश्यक कार्रवाई करें:

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं तथा इसको लागू करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:

- सिनेमा हाल में राष्ट्रीय गान बजने से पहले प्रवेश और निकास दरवाजे बंद होने चाहिए ताकि राष्ट्रीय गान के प्रसारण में किसी भी तरह का व्यवधान ना आये, जो कि राष्ट्रीय गान का एक तरह से अपमान होगा।
- राष्ट्रीय गान तथा इसके किसी भी भाग को इस ढंग से प्रकाशित करना जो इसकी प्रतिष्ठा को किसी भी तरह से ठेस पहुचाये, राष्ट्रीय गान का अपमान माना जायेगा।
- वित्तीय लाभ के लिए राष्ट्रीय गान का किसी भी तरह से व्यावसायिक दोहन प्रतिबंधित है। राष्टीय गान का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है जिससे उसे किसी भी तरह का व्यावसायिक लाभ हो।
- राष्ट्रीय गान का किसी भी तरह का नाटकीय रूपांतरण, किसी भी तरह के शो या सेमिनार में नहीं किया जा सकता। यह इसलिए है क्योकि जब राष्ट्रीय गान बजता है तो यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह उसका सम्मान करे और राष्ट्रीय गान के नाटकीय रूपांतरण के बारे में सोचना पूर्णतया अकल्पनीय है।
- भारत के सभी सिनेमा हॉल के लिए किसी भी फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य है तथा सिनेमा हॉल में उपस्थित सभी लोगों का राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़ा होना भी अनिवार्य है।
- हाल ही में दिव्यांगों को राष्ट्र गान के समय खड़े होने से छूट प्रदान की गयी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की संवैधानिक वैधता:

- हाल का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, तथा अमितव रॉय की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका के आधार पर दिया था। यह दिशा निर्देश मातृभूमि के लिए प्यार तथा सम्मान के आधार पर दिए गए हैं । कोर्ट ने यह उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्यार और सम्मान देश के प्रति प्यार और सम्मान को दर्शाता है।
- इसके अलावा यह देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद की भावना का भी संचार करता है। संविधान के अनुच्छेद 51(A)(a) के तहत यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारतीय संविधान का पालन करे तथा संविधान के आदर्शो तथा संस्थाओं,राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे। यह भारत के संविधान में लिखित है इसीलिए यह हर एक भारतीय का निजी कर्तव्य है।

चिकनगुनिया का पहला टीका विकसित:

- वैज्ञानिकों ने चिकनगुनिया के बुखार का पहला टीका विकसित कर लिया है। यह टीका एक खास वायरस से तैयार किया गया है, जिसका इंसानों पर कोई असर नहीं होता है। इस लिहाज से यह कारगर भी है और प्रभावी भी।
- इसे **'ईलैट' या 'अल्फा वायरस'** कहते हैं। यह वायरस इंसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता जबकि चिकनगुनिया पर पूरी तरह प्रभावकारी होता है। चूहों और अन्य स्तनधारियों पर शोध में पाया गया कि चिकनगुनिया से

पीड़ित जीव को यह टीका लगाने पर उसके शरीर में मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होता है और बीमारी से उसकी सुरक्षा करता है।

- टेक्सास विश्वविद्यालय में औषधि विभाग के वरिष्ठ शोधकर्ता स्कॉट वेवर ने बताया कि यह टीका सुरक्षित और प्रभावकारी है। जिस वायरस से इसे विकसित किया गया है, वह केवल कीटों को प्रभावित करता है। लिहाजा यह बहुत महंगी भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ईलैट के क्लोन से हाईब्रिड वायरस बनाया जो मच्छरों द्वारा फैलाए गए चिकनगुनिया वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। यह एंटीबॉडी 290 दिनों तक प्रभावकारी रहती है और वायरस से सुरक्षा करती है।

क्या है चिकनगुनिया?

यह एडिस मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरस है। इससे शुरुआत में तेज बुखार होता है जो कई दिनों तक बना रहता है। इस बीमारी में बुखार और जोड़ों में भारी दर्द होता है। चिकनगुनिया के चलते सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द-सूजन और कभी-कभी रैशेज भी हो जाते हैं। इस बीमारी का असर लंबे समय तक बना रहता है, जिसके चलते जोड़ों में दर्द रहता है।

चिकनगुनिया का दुनिया में प्रभाव:

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, यह वायरस एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के कई देशों में फैला हुआ है। अमेरिका में इसके अब तक कम ही मामले सामने आए हैं, जबकि यूरोपीय देशों में केवल इटली में यह पाया गया है। इस वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव एशियाई देशों में दिखाई देता है।

प्रभावित देशों की स्थिति:

40 देशों में फैला है चिकनगुनिया वायरस का प्रभाव। 1952 में सबसे पहले तंजानिया में हुई थी इसकी खोज। 2006 में सिर्फ एशिया में करीब तीन लाख लोग पीड़ित मिले।

व्यापार सुगमता के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों को चिन्हित किया

व्यापार सुगमता के लिहाज से 50 शीर्ष देशों की सूची में शामिल होने के प्रयास के तहत सरकार ने उन क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहां जटिल नियमों को समाप्त करते हुए प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत है ताकि कोई भी कंपनी चार दिन में अपना काम शुरू कर सके। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक के व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत को 190 देशों में से **130वें** स्थान पर रखा गया है।

- इस पहल का उद्देश्य देश में व्यापार माहौल को सुधारना तथा इसकी रैंकिंग सुधारना है ताकि किसी भी कंपनी को उद्यम शुरू करने के लिए कम से कम समय की जरूरत हो और उसे आसान रिण उपलब्ध हो।
- आधिकारिक बयान के अनुसार ईबिज पोर्टल -श्रम सुविधा- कारपोरेट कार्य मंत्रालय से जुड़े मामलों के लिए एकल खिड़की जैसी सुविधा प्रदान करेगा। इसमें पैन:टैन के लिए पंजीकरण तथा कर्मचारी भविष्य निधि: कर्मचारी बीमा जैसे काम भी शामिल है।
- इसके अनुसार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सीबीडीटी, श्रम व रोजगार मंत्रालय मिलकर काम करेंगे ताकि कोई कारोबार शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं की संख्या घटाकर चार की जा सके। साथ ही इसमें लगने वाले दिनों की संख्या भी घटाकर चार की जा सके। फिलहाल भारत में कोई कंपनी शुरू करने में कम से कम तीन सप्ताह का समय लगता है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट:

- साल 2016 की विश्व बैंक द्वारा जारी की गई दुनियाभर में आसानी से कारोबार करने की रैंकिंग सूची में भारत का नंबर 130वें स्थान पर है। यह रैंक कुल 190 देशों की सूची में भारत ने हासिल की है। पिछले साल की सूची में भारत 131वें स्थान पर था।
- कारोबारी सुगमता की यह सूची हर साल जारी की जाती है। रैंकिंग तय करने के लिए लगभग 10 पॉइंट्स या पैमानों पर किसी भी देश को तौला जाता है। रैंकिंग **बिजली की उपलब्धता, विनिर्माण मंजूरियां, लागत, आपूर्ति, प्रक्रियाओं की संख्या, समय, ऋण हासिल करने, कारोबार शुरू करने** जैसी चीजों को ध्यान में रखकर तय की जाती है।

भारत-अरब साझेदारी सम्मेलन का 5वां संस्करण मस्कट, ओमान में आयोजित:

पांचवें भारत-अरब साझेदारी सम्मेलन (5th India-Arab Partnership Conference) का आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य:

- सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और अरब देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देना, निवेश परियोजनाओं की गति बढ़ाना ,मौजूद संयुक्त उपक्रमों को सक्रिय करना तथा निर्यात संवद्र्धन के अनुकूल माहौल बनाना है। फिक्की और औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) का संयुक्त उपक्रम इन्वेस्ट इंडिया और राज्य सरकारें अरब देशों को भारत में निवेश की संभावनाओं पर अपनी प्रस्तुति देंगी।
- अरब देश संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े कारोबारी साझेदार हैं। अरब देशों तथा भारत के बीच 180 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार है। भारत अपनी 60 फीसदी तेल एवं गैस की जरूरतों की पूर्ति पश्चिम एशिया से करता है। विभिन्न कारोबार करने वाली कई भारतीय कंपनियां इस कारोबार का हिस्सा हैं।

शहरी विकास पर एशिया-प्रशांत सम्मेलन

- एशिया-प्रशांत आवास एवं शहरी विकास मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अंत में 16 दिसम्बर 2016 को जारी**'दिल्ली घोषणा'**में स्वीकार किया गया है कि समाज के प्रत्येक तबके की पहुंच में आ सकने वाले आवासों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सके। शहरी नियोजन को आस पास के क्षेत्रों तक तथा गांवों तक बढाया जाना चाहिए जिससे समाज का समग्र विकास किया जा सके।
- इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के 68 देशों के लगभग 1250 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और भविष्य के शहरी नियोजन की रणनीति तय करने के अलावा आवास के क्षेत्र में आपसी अनुभव भी साझा किए। इस सम्मेलन का उद्घाटन शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने किया था।
- दिल्ली घोषणा में कहा गया है कि शहरी आवास को सरल, समग्र और सतत् बनाने की जरुरत है। समाज के समस्त वगरें के विकास के लिए शहरों में नियोजन आवश्यक है जिसमें आबादी, बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण के बीच समंवय पर जोर देना होगा। सम्मेलन में औपचारिक तौर पर भारत को 68 देशों के इस समूह के अगले दो साल के लिए नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गयी।
- इस दौरान शहरी ग्रामीण योजना एवं प्रबंधन, झुग्गियों एवं अन्य बस्तियों का विकास, आधारभूत सेवा, आवास वित्त और प्राकृतिक एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदा के संदर्भ में शहरी विकास पर विचार विमर्श किया गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कुल 60 प्रतिशत आबादी और 55 प्रतिशत शहर आबादी निवास करती है। इससे पहले यह सम्मेलन दिल्ली में 10 साल पहले वर्ष 2006 में आयोजित किया गया था।
- घोषणा पत्र में**'अर्बन प्लस'**पद्धति पर जोर देते हुए कहा गया है कि शहरी नियोजन में आस पास के क्षेत्रों और अनौपचारिक विस्तार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शहरों को एक स्वतंत्र निकाय समझने की बजाय शहरी ग्रामीण परिवेश में समझा जाना चाहिए और इसके अनुरुप नियोजन करना चाहिए।

टीबी, एचआईवी, मलेरिया से लड़ने के लिए अनुसंधान में लाई जाए तेजी : ब्रिक्स

ब्रिक्स देशों ने टीबी, एचआईवी एवं मलेरिया जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए अनुसंधान में तेजी लाने और समय पूर्व मृत्य दर को कम करने के लिए कदम उठाने पर 16 दिसंबर 2016 को सहमति जताई। इसके साथ उन्होंने किफायती उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता पर भी बल दिया।

- ब्रिक्स के स्वास्थ्य मंत्रियों की समाप्त हुई छठी दो दिवसीय बैठक में उन्होंने दिल्ली विज्ञप्ति को पारित किया, जिसके तहत सदस्य देशों ने एक टीबी सहयोग योजना, टीबी अनुसंधान पर एक ब्रिक्स नेटवर्क और टीबी, एचआईवी एवं मलेरिया पर एक अनुसंधान एवं विकास संकाय विकसित करने पर बात की।
- 25 बिंदुओं वाली इस विग्यप्ति में दवाइयों एवं नैदानिक उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास, सतत विकास लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक गैर संक्रामक बीमारियों के कारण होने वाली समय पूर्व मृत्यु दर को एक तिहाई तक कम करने और प्रभावशाली स्वास्थ्य निगरानी की बात पर जोर दिया गया है।
- दुनिया की 43 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स गठबंधन के पांच देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई कदमों पर सहमति बनी है। इसमें टीबी, एचआइवी और मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए साझा कार्यक्रम बनाने के साथ ही शोध और अनुसंधान में करीबी सहयोग का ढांचा तैयार करना भी शामिल है।
- इन देशों का कहना है कि ये ऐसी बीमारियां हैं जिन पर शोध भी इन्हीं को करना होगा। इनके लिए गुणवत्तापूर्ण दवा, टीके और जांच आदि को विकसित करने के लिए इन देशों को आपसी सहयोग बढ़ाना होगा। इस दौरान **'ब्रिक्स टीबी सहयोग योजना'** को अपनाने पर भी सहमति बनी। इसके तहत 'ब्रिक्स नेटवर्क ऑन टीबी रिसर्च' शुरू किया जाना है। साथ ही टीबी, एचआइवी और मलेरिया पर शोध और विकास के लिए एक कंसोर्टियम तैयार करने को ले कर भी सहमति बनी है। यह बीमारियों के लिए यह कंसोर्टियम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन जुटाने की कोशिश भी करेगा। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया।

भारत ने छह देशों के साथ खुला आकाश समझौतों पर हस्ताक्षर किया है:

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन वार्ताएं (आईसीएएन) – 2016 में आयोजित की गईं। नागरिक उड्डयन सचिव आर.एन. चौबे ने बताया कि आईसीएओ के 191 देशों में से 106 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने 17 देशों के साथ बातचीत की और 12 देशों के साथ सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी 2016) में दिये गये निर्देशों के मुताबिक अनेक प्रमुख मुद्दे सुलझाये गयेः

यातायात अधिकारों में वृद्धिः

भारत ने ओमान के साथ यातायात अधिकारों पर फिर से बातचीत की, जिससे हकदारी में वृद्धि सुनिश्चित हुई है। इसके तहत वर्ष 2017 के ग्रीष्म ऋतु से 6258 सीटें प्रभावी हो जाएंगी, क्योंकि मौजूदा हकदारी कमोबेश समाप्त हो गई है। भारत ने आईएटीए सीजन से क्षमता में प्रति सप्ताह 8000 सीटों की वृद्धि के लिए सऊदी अरब से सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच यातायात में बढ़ोतरी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है।

एनसीएपी 2016 के मुताबिक खुला आकाश समझौताः

- इस दौरान छह देशों के साथ खुला आकाश समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये, जिनमें **जमैका, गुयाना, चेक गणराज्य, फिनलैंड, स्पेन और श्रीलंका** शामिल हैं।
- खुला आकाश समझौते में छह महानगरों जैसे कि **दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरू और चेन्नई** स्थित हवाई अड्डों तक असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति दी गई है। नई व्यवस्था से भारत और इन देशों के बीच कनेक्टिविटी के साथ-साथ यात्रियों के सफर को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।

- नये हवाई सेवा समझौतों पर जमैका एवं गुयाना के साथ हस्ताक्षर किये गये। घाना, इजरायल, जापान, मलेशिया, पुर्तगाल, हांगकांग, इथियोपिया और बांग्लादेश के साथ हवाई सेवा समझौते से संबंधित अन्य मसलों को भी सुलझाया गया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस: 24 दिसम्बर

- उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (National Consumer Day) के रूप में मनाया जाता है यह दिन 24 दिसंबर के दिन इस लिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इस वर्ष का विषय "वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया" है।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं में जागरूता फैलाना है और उनके हितों की रक्षा एवं उन्हें विभिन्न प्रकार के शोषण से बचाना है।

प्रधानमंत्री ने रखी शिवाजी स्मारक की आधारशिला

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 दिसम्बर 2016 को मुंबई तट पर स्थित अरब सागर के एक द्वीप पर छत्रपति शिवाजी स्मारक की आधारशिला रखी।
- करीब 15 एकड़ के द्वीप पर प्रस्तावित स्मारक समंदर में किनारे से डेढ किलोमीटर अंदर होगा।
- इस स्मारक मे शिवाजी महाराज का जो पुतला होगा उसकी ऊंचाई घोड़े समेत 192 मीटर है। घोडे पर बैठे हुए छत्रपती शिवाजी महाराज के पुतले की उंचाई 114.4 मीटर है।
- ये स्मारक करीब 13 हेक्टेयर के चट्टान पर होगा। परियोजना की कुल लागत 3600 करोड़ रूपये है जिसमें से पहले चरण की लागत 2500 करोड़ रूपये होगी।

देहरादून में बैंकिंग लोकपाल ऑफिस

- रिजर्व बैंक ने देहरादून में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला है। इस तरह अब देश में कुल बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। बैंकिंग नेटवर्क में अच्छी खासी बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसा किया गया है। देहरादून ऑफिस कानपुर कार्यालय का बोझ कम करने में सहयोग करेगा।
- आरबीआई ने एक बयान में कहा कि पिछले कुछ समय में बैंकिंग नेटवर्क में विस्तार और कानपुर ऑफिस पर भारी बोझ को देखते हुए देहरादून ऑफिस खोला गया है। उत्तर भारत में कानपुर और चंडीगढ़ के बाद यह तीसरा लोकपाल ऑफिस है।
- देहरादून ऑफिस के कार्य क्षेत्र में उत्तराखंड के अलावा यूपी के सात जिले भी आएंगे। यूपी के इन सात जिलों के नाम **सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा** है। बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में बैंकों के कामकाज के बारे में शिकायत की जाती है।

"टैनसेट" उपग्रह का प्रक्षेपण

- चीन ने को वैश्विक कार्बन उत्सर्जन पर निगरानी रखने के लिए लांग मार्च-2डी रॉकेट के जरिए "टैनसेट" उपग्रह प्रक्षेपित किया। यह गोबी रेगिस्तान स्थित जिउकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।
- चाइना एकेडमी ऑफ साइसेंज के माइक्रो- सैटेलाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख टैनसेट डिजाइनर यिन जेंगशान ने बताया कि 620 किलो वजनी "टैनसेट" उपग्रह धरती से 700 किलोमीटर ऊपर सूरज की समकालिक कक्षा में भेजा गया है जो वातावरण में एकाग्रता, वितरण और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाह की निगरानी करेगा। इस उपग्रह से जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद मिलेगी, साथ ही यह स्वतंत्र डेटा भी उपलब्ध कराएगा।

- अपने तीन साल के मिशन के दौरान यह हर 16 दिनों में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का अच्छी तरह से निगरानी करेगा। जापान और अमेरिका के बाद उपग्रह के जरिए ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करने वाला चीन तीसरा देश है।

खुले में कचरा जलाने पर एनजीटी ने रोक लगायी

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में खुले में कचरा जलाने पर देश भर में रोक लगाने का आदेश दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों को पांच हजार से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। एनजीटी प्रमुख जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 दिसम्बर 2016 को यह आदेश दिया।
- हाल में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई थी। एनजीटी के फैसले के बाद कचरा निस्तारण वाले स्थान पर भी इसे खुले में नहीं जलाया जा सकेगा। अलमित्र पटेल की अर्जी पर यह व्यवस्था दी गई है।
- एनजीटी ने इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने पोलीविनाइल क्लोराइड (फ्लेक्स) और प्लास्टिक (क्लोरिनेटेड) के इस्तेमाल पर रोक को लेकर पर्यावरण मंत्रालय और सभी राज्यों को छह महीने के अंदर उचित निर्देश जारी करने को कहा है।

उत्तर प्रदेश में 17 पिछड़ी जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल

- यूपी कैबिनेट ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का फैसला किया है। **इन जातियों में कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, भीवर, बिंद, भर, राजभर, बाथम, तुरहा, गोंड, मांझी, मछुआरा जातियां शामिल हैं।**
- इसे मुद्दा बनाने के लिए अखिलेश सरकार केंद्र की मोदी सरकार के पास संस्तुति के लिए यह प्रस्ताव भेजेगी।
- विदित हो कि वर्ष 2005 में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अन्य पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जाती में बदलने का प्रस्ताव पारित किया था जिसे केंद्र ने अपने अधीन पॉवर के तहत खारिज कर दिया था। इस प्रस्ताव को बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने गैर संवैधानिक घोषित कर खारिज कर दिया था। आपको बता दे कि अनुसूचित जाती में बदलाव केंद्र की सत्ता के अधीन आता है।

क्रूज मिसाइल निर्भया का प्रक्षेपण

- ओडिसा में चांदीपुर के एकीकृत मिसाइल टेस्ट रेंज से भारत ने 21 दिसम्बर 2016 को परमाणु वहन क्षमता से युक्त **लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइल 'निर्भया' का प्रक्षेपण किया**।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस मिसाइल को सुबह 11 बजकर 56 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया। परमाणु वहन की क्षमता से युक्त यह मिसाइल 700 – 1000 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बना सकती है और रडॉर के जरिये इसे पकड़ पाना मुश्किल होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी

- फॉर्ब्स मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी। भारत को यह उपलब्धि 150 साल में पहली बार प्राप्त हुई है। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में ब्रिटेन भी अब भारत से पीछे है। **भारत अमेरिका, चीन, जापान व जर्मनी के बाद पांचवीं सबसे बड़ी जीडीपी बन गया है**।
- पिछले 25 साल में भारत की तेज इकॉनॉमिक ग्रॉथ और वर्ष भर में पाउंड के मूल्य में आई कमी के कारण यह परिवर्तन हुआ है। इसका कारण ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने और भारत की तेज विकास दर को माना जा रहा है।
- फॉर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार भारत द्वारा 2020 तक ब्रिटेन की जीडीपी को पार करने का अनुमान था। पिछले 12 महीने में पाउंड के मूल्य में लगभग 20 प्रतिशत की कमी ने यह 2016 में कर दिया।

- ब्रिटेन की 1.87 ट्रिलियन पाउंड की जीडीपी एक डॉलर के मुकाबले 0.81 पाउंड की एक्सचेंज रेट पर 2.29 ट्रिलियन डॉलर में बदलती है। भारत की 153 ट्रिलियन रुपये की जीडीपी एक डॉलर के मुकाबले 66.6 रुपये से बदलने पर 2.30 ट्रिलियन डॉलर होती है।

'कोल मित्र' वेब पोर्टल लॉन्च

- डोमेस्टिक कोल के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए 'कोल मित्र' वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को केंद्रीय कोयला और विद्युत मंत्री पीयुष गोयल ने लांच किया। इस मौके पर उन्होंने 'रिन्यूवेबल एनर्जी इंटिग्रेशन' समेत कई रिपोर्ट्स भी जारी कीं।
- 'कोल मित्र' वेब पोर्टल को डोमेस्टिक कोल के इस्तेमाल को आसान और सरल बनाने के लिए लाया गया है। इसके जरिए रिजर्व्स को कम खर्चे में सबसे कुशल स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता है। ये स्टेशंस राज्य/केंद्र या प्राइवेट सेक्टर किसी के भी हो सकते हैं। इससे न सिर्फ खर्चे में कमी आएगी, बल्कि कंज्यूमर्स का लाइट बिल भी कम होगा।

राष्ट्रीय गणित दिवस: 22 दिसम्बर

- प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर के दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन के जन्म दिवस को पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस (National Mathematics Day) के रूप में मनाया जाता है।
- इस दिवस का अवलोकन सबसे पहले 26 फरवरी, 2012 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। यह घोषणा रामानुजन की 125 वीं जयंती के अवसर पर मद्रास विश्वविद्यालय में की गयी थी।

माजुली द्वीप के संरक्षण और विकास के लिए केंद्र सरकार ने 207 करोड़ रुपये जारी किये

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने असम में ब्रम्हापुत्र नदी के साथ स्थित विश्व विरासत द्वीप माजुली के संरक्षण और विकास के लिए 207 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
- दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली द्वीप, 340 मील के क्षेत्र में है। लगभग 1 लाख 60 हजार लोग इस द्वीप पर रहते हैं और यह पूर्वोत्तर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह द्वीप नव-वैष्णव संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र भी है जिसकी शुरुआत श्रीमंत शंकरदेव ने की थी।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पोस्को ई-बॉक्स के लिए पुरस्कार से सम्मानित

- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को पोस्को ई-बॉक्स के लिए स्काच सिल्वर और स्काच आर्डर ऑफ मैरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।** यह पुरस्कार पिछले सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपर सचिव अजय कुमार ने एनसीपीसीआर की अध्यक्ष स्तुति कक्कड़ को प्रदान किया।
- कार्यक्रम में टेक्नॉलोजी कंपनियों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और अनुसंधान संगठनों ने भाग लिया। एनसीपीसीआर को यह पुरस्कार बाल यौन शोषण की शिकायत पंजीकृत करने के लिए इलेक्ट्रानिक ड्राप बॉक्स पोस्को ई-बॉक्स विकसित करने में प्रौद्योगिकी के उपयोग करने हेतु प्रदान किया गया है।

गर्व 2 मोबाइल एप्प और नागरिकों को जोडने वाली खिड़की 'संवाद' शुरू

- गांवों के विद्युतीकरण के बाद हर घर बिजली पहुँचाने के सपने को साकार करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने 20 दिसम्बर 2016 को गर्व 2 मोबाइल एप्प लांच की। इससे पहले 2015 में देश के हर गांव को बिजली से जोड़ने के लिए गर्व एप्प लांच की गई थी।

- इस तरह की डिजिटल पहल से सरकार रियल टाइम में विद्युतीकरण की प्रक्रिया पर पारदर्शी तरीके से नज़र रख सकती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के हर घर में बिजली पहुंचे और हर बच्चा रोशनी के अभाव में पढ़ने से न चूक जाये, इसकी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।
- जीएसआरवी-दो में नागरिकों को जोडऩे वाली व्यवस्था **'संवाद'** होगा जिसका मकसद उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। वे अपनी राय और सुझाव देकर कार्यक्रम में अपना योगदान दे सकते हैं। उनके सुझाव सीधे एसएमएस और ईमेल के जरिये डिसकॉम के प्रबंध निदेशकों तथा अधीक्षण अभियंता के डैशबोर्ड पर जाएगा।

केंद्र ने अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एक स्थायी न्यायाधिकरण गठित करने का फैसला

- केंद्र ने सभी अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए सभी न्यायाधिकरणों को मिलाकर एक स्थायी न्यायाधिकरण गठित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य तेज रफ्तार से राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करना है।
- सरकार ने जरूरत पड़ने पर विवादों पर गौर करने के लिए अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन कर पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया है। अधिनियम में संशोधन को मंजूरी का फैसला इस हफ्ते हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। संशोधन को संसद के अगले सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
- जल संसाधन मंत्रालय के सचिव शशि शेखर ने कहा कि केवल एक स्थायी न्यायाधिकरण होगा, जिसके प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। जरूरत पड़ने पर पीठें गठित की जाएंगी। विवाद सुलझने पर वह पीठ अस्तित्व में नहीं रहेगी। शेखर ने कहा कि जल न्यायाधिकरणों ने विवादों में अंतिम फैसला सुनाने के लिए काफी समय लिया, जबकि प्रस्तावित न्यायाधिकरण के 3 साल में अपना फैसला सुनाने की संभावना है।

'भारतीय कौशल संस्थान'

- युवकों को अधिक रोजगार पाने योग्य एवं स्वनिर्भर बनने के लिए उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के द्वारा भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के अपने विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में देश के अब तक पहले **'भारतीय कौशल संस्थान'** की आधारशिला रखी। इस संस्थान की संकल्पना नरेन्द्र मोदी द्वारा सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की यात्रा के दौरान की गई थी।

- **केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साझेदारी में देश में अपनी तरह के ऐसे पहले संस्थान की स्थापना करने का फैसला किया है। यह संस्थान प्रशिक्षण के सिंगापुर मॉडल से प्रेरित है और यह देश के विभिन्न सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को अंगीकार करेगा। मंत्रालय ने ऐसे 6 संस्थान खोलने का निर्णय किया है।**

भारत विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा पैदा करने वाले देशों में चौथे स्थान पर:

- 28,279 मेगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ भारत, दुनिया में **चीन, अमरीका और जर्मनी** के बाद चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश बनकर उभरा है।
- भारत ने 2015-16 में 3,423 मेगावाट की विशालतम पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की है। 2016-17 के दौरान 1,502 मेगावाट क्षमता 31 अक्टूबर 2016 तक जुड़ चुकी थी जिसने कि संचयी ऊर्जा को 28,279 मेगावाट बना दिया।

राजीव जैन खुफिया ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त:

- झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव जैन को खुफिया ब्यूरो (आईबी) के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।

- जैन, जो वर्तमान में आईबी में विशेष निदेशक के रूप में उपस्थित है, 31 दिसंबर 2016 को दिनेश्वर शर्मा के दो वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद 1 जनवरी, 2017 से पदभार संभालेंगे।

एके धस्माना रॉ के चीफ नियुक्त:

- अनिल धस्माना बाह्य खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के नए प्रमुख होंगे। इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
- वह इस साल राजिंदर खन्ना, के कार्यकाल के सफलतापुर्वक समापन के बाद,अनिल धस्माना पदभार संभालेंगे।

लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत अगले सेना प्रमुख, बी.एस धनोआ भारतीय वायुसेना के प्रमुख नियुक्त

- आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल **बिपिन रावत आर्मी स्टाफ के नए प्रमुख** बनेंगे,जबकि **एयर मार्शल बी एस धनोआ,** एयर स्टाफ के अगले चीफ होंगे।
- वे दोनों इस दिसम्बर महीने की 31 तारीख की दोपहर से पद संभालेंगे।
- लेफ्टिनेंट जनरल रावत जनरल दलबीर सिंह का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल के पास पिछले तीन दशकों से युद्ध क्षेत्रों में और भारतीय सेना में विभिन्न कार्यात्मक स्तरों पर सेवा करने का अनुभव है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ LoC, चीन के साथ LAC, और उत्तर-पूर्व सहित, कई क्षेत्रों में विभिन्न परिचालन जिम्मेदारियों को संभाला है।
- एयर मार्शल धनोआ, जो एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अरूप राहा का स्थान लेंगे, जून 1978 में वायु सेना के लड़ाकू धारा में साधिकारकिया गया था। उन्होंने विभिन्न स्क्वाड्रनों में वायुसेना मुख्यालय के खुफिया निदेशालय में भी सेवा की है।

थाल फावांग कुत त्यौहार मिजोरम में शुरू

- पर्यटन विभाग, मिजोरम सरकार द्वारा आयोजित थाल फावांग कुत त्यौहार उत्साह और जोश के साथ मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल में शुरू किया गया है। यह फसल कटाई के बाद का त्योहार है, जो धान की कटाई के बाद मनाया जाता है।
- यह सर्वशक्तिमान का शुक्रिया अदा करने के साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है।

ब्रिटेन में थ्री पैरेंट बेबीज पहल की मंजूरी

- ब्रिटेन के प्रजनन नियामक प्राधिकरण ने ऐतिहासिक फैसले में एक विवादित तकनीक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अगले वर्ष से देश में 'तीन माता-पिता' वाले बच्चे पैदा हो सकेंगे। प्रजनन नियामक 'ह्यूमन फर्टिलाइजेशन ऐंड एम्ब्रायोलॉजी अथॉरिटी' (HFEA) ने तीन लोगों के आईवीएफ को मंजूरी दे दी है।
- इस तकनीक के माध्यम से बच्चे में जानलेवा अनुवांशिक बीमारियों को आने से रोका जा सकेगा। दो महिलाओं और एक पुरुष से बने ऐसे पहले बच्चा अगले वर्ष इन्हीं दिनों जन्म लेगा। इस तकनीक का प्रयोग कर जन्म लेने वाले बच्चों में अपने माता-पिता के जीन के अलावा तीसरी मां के डीएनए का कुछ हिस्सा होगा। HFEA अध्यक्ष सैली चेशर ने कहा, 'यह ऐतिहासिक महत्व का फैसला है।
- नियमों के अनुसार, इस दुर्लभ प्रक्रिया को अपनाने से पहले प्रत्येक क्लिनिक और प्रत्येक मरीज को प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। क्लिनिक अब 'तीन व्यक्ति आईवीएफ' के विस्तृत प्रयोग के लिए लाइसेंस प्राप्ति के लिए HFEA में आवेदन कर सकते हैं।

भारत की पहली 2 जी एथेनॉल बायो रिफाइनरी का शिलान्यास

- भारत की पहली 2 जी एथेनॉल बायो रिफाइनरी का 25 दिसम्बर 2016 को बठिंडा में शिलान्यास किया गया |

- इस एथेनॉल बायो रिफाइनरी की अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है |इस परियोजना की स्थापना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई है |

मुख्य बिंदु

- इस सार्वजनिक उपक्रम से मालवा क्षेत्र के २० लाख किसानों को लाभ होगा |
- बठिंडा में प्रत्येक वर्ष तीन लाख किसान पराली बेचकर 20 करोड़ से अधिक की कमाई करेंगे जबकि पुरे मालवा में 300 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिल सकेगा |
- इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा क्योंकि लोगों को धन की फसल के बाद पराली जलने से होने वाले धुंए के प्रदूषण से रहत मिलेगी |
- सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों तथा भारत सरकार की और से देश भर में इस प्रकार की 12 एथनॉल रिफाइनरी 11 राज्यों में स्थापित की जाएगी |
- पंजाब , हरियाणा , उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , बिहार , असम,ओडिशा,गुजरात ,महाराष्ट्र , कर्नाटक में 12 जैव रिफाइनरियों के लिए अनुमानित निवेश 10000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है |
- पेट्रोल में मिलाने के लिए 10 प्रतिशत एथेनॉल इस रिफाइनरी में तैयार किया जाएगा |

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों का लक्ष्य प्राप्त किया:

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों का लक्ष्य 8 माह से भी कम अवधि के भीतर ही हासिल कर लिया गया है और यह योजना अब 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है।

मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए तय 1.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों का लक्ष्य 8 माह से भी कम अवधि के भीतर ही हासिल कर लिया गया है।
- अधिकतम कनेक्शनों वाले शीर्ष 5 राज्य ये हैं: उत्तर प्रदेश (46 लाख), पश्चिम बंगाल (19 लाख), बिहार (19 लाख), मध्य प्रदेश (17 लाख) और राजस्थान (14 लाख)। अब तक जारी किये गये कुल कनेक्शनों में लगभग 75 फीसदी हिस्सा इन्हीं पांचों राज्यों का है।
- लाभार्थियों में बड़ी संख्या एससी/एसटी परिवारों की ही है। 35 फीसदी कनेक्शन इन्हीं परिवारों को जारी किये जा रहे हैं।
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकता वाले राज्यों के रूप में राष्ट्रीय औसत से कम एलपीजी कवरेज वाले 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की पहचान की गई है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)के बारे में

- "स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ केंद्र सरकार नें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक सामाजिक कल्याण योजना – "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" की शुरूआत की।

- यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अगले 3 साल के लिए 8000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों के लिए 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 1600 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ प्रदान करेगा। 2016 के बजट भाषण में योजना के बारे में घोषणा की गई और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2000 रुपये करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया। कनेक्शनों को महिला लाभार्थियों के नाम पर जारी किया जायेगा।
- चूल्हे एवं रिफिल की लागत के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान की जायेगी। यह प्रधानमंत्री के गिव इट अभियान के मानार्थ है जिसके तहत 75 लाख मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों नें स्वेच्छा से अपने रसोई गैस सब्सिडी को छोड़ दिया है।

केंद्र ने 99 चिन्हित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रोड मैप तैयार किया:

- केंद्र सरकार ने 29 दिसम्बर 2016 को एक्सेलेरेटेड इरिगेशन बेनेफ्ट्सि प्रोग्राम (एआईबीपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 99 सिंचाई परियोजनाओं के जल्द पूरा होने का खाका तैयार किया है।
- इन 99 परियोजनाओं में से अधिकतम 26 महाराष्ट्र में आठ आंध्र प्रदेश में और एक गुजरात में है।
- इन परियोजनाओं में केंद्र ने 2016-17 तक 23 परियोजनाओं को पूरा करने और 2017-18 तक 31 परियोजनाओं को पूरा करने का उद्देश्य रखा है। विज्ञप्ति के मुताबिक, बाकी 45 परियोजनाएं दिसंबर 2019 तक पूरी होंगी।
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) ने इन परियोजनाओं के लिए 3,274 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिनमें 1,981 आंध्र प्रदेश, 830 करोड़ रुपये महाराष्ट्र और 463 करोड़ रुपये गुजरात के लिए आवंटित हैं।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई, 2015 में पूरे भारत में पीएमकेएसवाई के लिए पांच वर्षो की अवधि तक 50,000 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश की सभी आठ परियोजनाओं को दूसरी श्रेणी में प्राथमिकता दी गई है, जिनमें गुजरात के सरदार सरोवर एकमात्र परियोजना है, जिसे तीसरी श्रेणी में जगह दी गई है। ये परियोजनाएं 2018 तक पूरी होंगी।
- इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 77,595 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी की जरूरत है।

पंचाट तंत्र के संस्थानीकरण की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन:

- भारत में न्याय वितरण प्रणाली विभिन्न अदालतों में विभिन्न कारणों की वजह से विशाल मात्रा में लंबित मामलों की वजह से अत्यधिक दवाब में आ गयी है।
- अन्याय, वाणिज्यिक विवादों में विशेष रूप से अधिक है, जहां मामले सालों से लंबित रहते हैं। तदनुसार, मध्यस्थता विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी और कुशल विकल्प प्रदान करता है।
- सरकार ने देश को मध्यस्थता केंद्र बनाने के उद्देश्य से मौजूदा मध्यस्थता व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा उपलब्ध सुविधाओं, संसाधनों आदि की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 29 दिसम्बर 2016 को बताया कि समिति वर्तमान मध्यस्थता व्यवस्था की दक्षता की समीक्षा एवं विश्लेषण के साथ वैकल्पिक विवाद समाधान संस्थानों के पास मौजूद सुविधाओं, संसाधनों तथा वित्त की उपलब्धता की भी समीक्षा करेगी।

- मध्यस्थता मामलों के समाधान के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों के काम की समीक्षा भी समिति के दायरे में होगी। यह समिति 90 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

वाम उग्रवाद से प्रभावित जिलों में सड़क विकास परियोजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी:

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी 90 प्रतिशत हिंसा से प्रभावित 35 जिलों और उनके आसपास के 9 जिलों में केन्द्र प्रायोजित सड़क विकास एवं निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए सड़कों का चुनाव राज्यों और सुरक्षा एजेंसियों से विचार विमर्श कर किया गया है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शुरु की जाने वाली इस परियोजना का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 44 जिलों और आसपास के क्षेत्रों में आवश्यक पुलिया और जल निकासी की व्यवस्था के साथ संपर्क स्थापित करना है।
- योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़के सभी मौसम में चालू रहेंगी। योजना के अंतर्गत पांच हज़ार चार सौ ग्यारह किलोमीटर से अधिक लम्बाई की सड़क और 126 सेतुओं के साथ जलनिकासी के निर्माण या मरम्मत का काम भी पूरा किया जाएगा।
- योजना के तहत धनराशी का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 60 और 40 के अनुपात में किया जाएगा। इसमें 8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्य शामिल नहीं होंगे।
- 2016-17 से 2019-20 तक वित्त मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय को 7 हज़ार 34 करोड़ 72 हज़ार रुपए का आवंटन करेगा। ग्रमीण विकास मंत्रालय इस योजना को प्रायोजित करने के साथ इसका कार्यान्वयन भी करेगा।

केन-बेतवा प्रॉजेक्ट को वाइल्डलाइफ बोर्ड की मंजूरी:

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने 26 दिसम्बर 2016 को घोषणा की कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी मिलने के साथ ही इसके मार्ग में अंतिम अड़चन खत्म हो गई। उमा ने कहा, इसके वित्तीय प्रबंधन को अंतिम रूप देने के बाद इसका औपचारिक निर्माण कार्य शुरू होगा।
केन बेतवा नदी जोडो परियोजना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो देश की विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने की 30 योजनाओं का सपना आंख खोलने लगेगा।

केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से लाभ:

- केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना पूरी होने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलाकर 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। विद्युत, मछलीपालन, पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही अच्छी बारिश के बाद केन नदी में आने वाली बाढ़ को भी रोका जा सकेगा। वन जीव बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। अब आठ महीने के भीतर काम शुरू हो सकता है।
- परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ मध्य प्रदेश को होगा। मध्य प्रदेश के 3,69,950 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के 2,65,700 हेक्टेयर भूमि को सींचा जा सकेगा।
- केन-बेतवा नदी को बरुआसागर में जोड़ा जाएगा। यह परियोजना पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी क्षेत्र से होते हुए गुजरेगी।
  गौरतलब है कि अच्छी बारिश न होने से बरुआसागर में झील का पानी नहीं भर पाता है। ऐसे में झरना भी नहीं चल पाता। इससे पर्यटकों का भी रुझान इस ओर कम हो रहा है। वहीं, केन नदी में पानी की अधिकता से बांदा में अकसर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ऐसे में केन-बेतवा नदी के गठजोड़ से एक तरफ बाढ़ को रोका जा सकेगा, दूसरी तरफ सूखे की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं, पर्यटकों को लुभाने में भी मदद मिलेगी।
- केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना सफल होती है, तो चार अन्य परियोजनाओं के भी शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस परियोजना पर कोसी-घाघरा, घाघरा-यमुना, शारदा-यमुना, गंडक-गंगा नदी गठजोड़ की निगाह टिकी हुई है। केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना को लेकर होने वाली बैठकों में भविष्य में नदियों को जोड़ने की योजना में इन नदियों पर चर्चा हुई है।

विश्व बैंक ने बिहार की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी:

विश्व बैंक ने बिहार ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 235 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह ऋण राज्य के ग्रामीण सड़क नेटवर्क के प्रबंधन में सुधार करने के लिए और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है।

मुख्य बिंदु

- परियोजना में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एमएमजीएसवाई) के तहत लगभग 2500 किमी की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। सड़कों का निर्माण लागत प्रभावी डिजाइन का उपयोग कर किया जाएगा और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। परियोजना में समय का बचाव करने के लिए बेहतर अनुबंध प्रबंधन के तरीकों का सुझाव भी दिया जाएगा और लागत में भी कमी जायेगी।
- यह ऋण ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD) को एक आधुनिक और उच्च प्रदर्शन वाली सड़क एजेंसी में बदल देगा। यह परियोजना लगभग 12 लाख लोगों को हर मौसम में सड़क तक पहुँच प्रदान करेगा, जिनमें से ज्यादातर समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के हैं। बिहार सरकार ने अपनी शीर्ष सात प्राथमिकताओं में "प्रत्येक बस्ती के लिए सड़क संपर्क" को भी रखा है।
- इसके अलावा, इस परियोजना का लक्ष्य शहर की राजधानी पटना से राज्य के सभी भागों की दूरी को पांच घंटों में तय करना है। यह क्रेडिट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) की ओर से दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में होनेवाला खर्च का इंतजाम राज्य को खुद करना पड़ता है। ग्रामीण कार्य विभाग ने अपना विजन 2020 तैयार किया है। इस विजन का मकसद है कि राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ दिया जाये।
- विश्व बैंक के सहयोग से इस साल एमएमजीएसवाइ में 2500 किलोमीटर सड़क बनना है। इसमें कम से कम दस फीसदी सड़क पीसीसी की जगह सेलफिल्ड तकनीक से बनेगा। अभी एक किलोमीटर सड़क के निर्माण पर 70 से 80 लाख का खर्च आता है।

सेलफिल्ड तकनीक:

- सेलफिल्ड तकनीक में मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक जाली होता है। इसी जाली में कंक्रीट को जमाया जाता है। विभागीय इंजीनियरों के अनुसार यह तकनीक कम खर्चीली होती है. यह पर्यावरण के भी अनुकूल है।
- इसमें पत्थर का भी कम प्रयोग होता है. जानकार बताते हैं कि जिस तरह पत्थरों की कमी हो रही एेसे में सड़कों के निर्माण में नयी तकनीक लानी होगी। विभागीय अधिकारी के अनुसार अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आनेवाले समय में विभाग पीसीसी की जगह से सेलफिल्ड तकनीक से सड़क बनायेगा। सड़क निर्माण में पॉलीमार का भी प्रयोग होगा।

देश की 95 करोड़ अबादी अब भी इंटरनेट से दूर

- डाटा प्लान और स्मार्टफोन की लगातार घटती कीमतों के बावजूद देश की 73 फीसदी आबादी यानी करीब 95 करोड़ लोग अभी भी इंटरनेट की सुविधा से दूर हैं। उद्योग संगठन एसोचैम और बाजार अध्ययन एवं सलाहकार कंपनी डेलॉएट के एक संयुक्त अध्ययन में यह बात सामने आई है।
- एसोचैम ने 'स्ट्रैटजिक नेशनल मेजर्स की कॉम्बैट साइबर क्राइम' नामक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि देश में इंटरनेट का दायरा बढ़ता जा रहा है तथा डिजिटल साक्षरता के विस्तार के लिए किफायती कीमत पर ब्रॉडबैंड, स्मार्टफोन तथा मासिक डाटा की उपलब्धता जरूरी है।

- रिपोर्ट के अनुसार, अभी देश में 34 करोड़ 30 लाख लोग इंटरनेट सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं जिसके वर्ष 2020 तक बढ़कर 60 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। इंटरनेट तक लोगों की पहुंच के मामले में भारत वैश्विक औसत से भी काफी पीछे हैं।
- रिपोर्ट के मुताबिक, सुदूर गांवों में डिजिटल सेवाएं देने के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण, वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी और प्रशिक्षण के काम में 'कौशल भारत योजना' के तहत प्रशिक्षित लोगों की मदद के जरिये डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जा सकती है।
- इसमें कहा गया है कि 'कौशल भारत' और 'डिजिटल भारत' के बीच तालमेल बिठाकर कार्यक्रम बनाने तथा प्रशिक्षण देने की जरूरत है। एसोचैम ने कहा है कि सरकार को लोगों को प्रौद्योगिकी के फायदों को समझाना चाहिए। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि इससे समाज के कमजोर वर्ग का जीवन स्तर किस प्रकार ऊंचा उठाया जा सकेगा।
- अध्ययन के अनुसार, "अधिकतर दूरसंचार कंपनियां अब तक ग्रामीण इलाकों में तेज गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए निवेश नहीं कर रही हैं। इसी तरह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों (एमएसएमई) को सरकार की योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है।"

अमरावती महास्तूप पुनर्जीवित किया जाएगा:

- देश के सबसे बड़े स्तूपों में से एक अमरावती महा स्तूप अमरावती महास्तूप को पुनरुद्धार किया जाएगा। हालांकि बौद्ध स्मारक अच्छी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है, लेकिन गंदगी, खुले सीवेज, सूअर और घरेलू कूड़े उसके आसपास के क्षेत्रों में होना लाजिमी है। इसलिए इसके अत्यधिक संरक्षण की आवश्यकता है।
- एएसआई, पीआरएएसएडी (तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विस्तार राष्ट्रीय अभियान) के अंतर्गत केंद्र द्वारा दिए गए फण्ड से स्तूप के बाहर परिवेश को साफ करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएगा।
- अमरावती आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है यह नगर सातवाहन राजाओं के शासनकाल में हिन्दू और बौद्ध संस्कृति का केन्द्र था। आंध्रवंशीय सातवाहन नरेश शातकर्णी ने लगभग 180 ई.पू. अमरावती को अपनी राजधानी बनाया। सातवाहन नरेश ब्राह्मण होते हुए भी महायान मत के पोषक थे।
- उन्हीं के शासनकाल में अमरावती का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप बना, जो तेरहवीं शताब्दी तक बौद्ध यात्रियों के आकर्षण का केन्द्र बना रहा।अमरावती स्थित महान बौद्ध स्तूप या महाचैत्य आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप था जिसका व्यास संभवत: 50 मीटर और ऊंचाई 27 मीटर थी।

मोबाइल भुगतान एप्लिकेशन भीम की शुरूआत

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को आधार आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) जारी किया। भीम सरकार के पुराने यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) और यूएसएसडी (अस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा) का ही नवीनीकृत रूप है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि भीम ऐप बिना इंटरनेट के भी काम करेगा।
- प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित ताकटोरा स्टेडियम में डिजी धन मेला कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। पीएम ने लकी ग्राहक योजना के विजेताओं के नाम की भी घोषणा की। भीम ऐप के उद्घाटन पीएम मोदी ने खादी ग्रामोद्योग से खरीदारी करके की। भीम ऐप को एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। माना जा रहा है कि ये ऐप प्लास्टिक कार्ड और पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन की जगह ले सकेगा और नकद-मुक्त अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान दे सकेगा।

भीम ऐप कैसे करेगा काम-

कारोबारियों को भीम ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना होगा। ये ऐप एक बॉयोमेट्रिक रीडर से जुड़ा होगा जिसकी कीमत बाजार में 2000 रुपये है। ग्राहक ऐप में अपना आधार नंबर और बैंक का नाम डालेंगे। उसके बाद बॉयोमेट्रिक स्कैन का पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करके उपभोक्ता भुगतान कर सकेंगे। करीब 40

करोड़ आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ा जा चुका है। सरकार ने मार्च 2017 तक सभी आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त:

- नजीब जंग के अचानक पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने अनिल बैजल को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। 1969 बैच के आईएएस रहे बैजल 2006 में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए थे। बैजल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के कार्यकारिणी समिति के सदस्य रह चुके हैं।
- बैजल रिटायरमेंट से पहले गृह सचिव, इंडियन एयरलाइंस के सीएमडी, प्रसार भारती के सीईओ और दिल्ली विकास प्राधिकारण यानी डीडीए के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। डीडीए का अध्यक्ष एलजी ही होते हैं जिस पद पर उनकी नियुक्ति की चर्चा है।
- बैजल यूपीए सरकार के दौरान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन से जुड़े रहे हैं। वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं।

बिहार में न्यायिक आरक्षण

- बिहार कैबिनेट ने बिहार में सभी स्तर की न्यायिक सेवाओं में 50 प्रतिशत पदों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया।
- बिहार न्यायिक सेवा में आरक्षण के नए प्रावधानों के तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा और बिहार असैनिक सेवा में होने वाली सभी नियुक्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।
- मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में किया गया।
- अब तक बिहार न्यायिक सेवा में कुल 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। जिसे अब बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21, पिछडा वर्ग के लिए 12, अनुसूचित जाति के लिए 16 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- इसमें सामान्य श्रेणी के अलावा सभी श्रेणियों में 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए तथा एक प्रतिशत पद अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। महिलाओं व दिव्यांगों को मिलने वाला आरक्षण सभी श्रेणी के कुल आरक्षित पदों में से 35 फीसद होगा।

नोटबंदी पर अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की:

- 28 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट रखने पर दंड दिए जाने के अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की।
- इस अध्यादेश द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों के प्रति सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक का दायित्व समाप्त हो जायेगा। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति से एक अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की गयी जिससे कि पुराने नोट पर आरबीआई के दायित्व को समाप्त किया जा सके।

अध्यादेश के प्रमुख तथ्य:

- किसी व्यक्ति के पास 500, 1000 रुपये के 10 से अधिक नोट पाए जाने पर सज़ा संभव होगी। पुराने नोट पाए जाने पर जेल का प्रावधान साफ़ नहीं किया गया लेकिन जब्त की गयी रकम का पांच गुना जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- यह सज़ा 31 मार्च 2017 के बाद से पाए जाने वाले नोटों पर लागू होगी। तय सीमा से अधिक नोट रखना आपराधिक मामलों की श्रेणी में माना जायेगा तथा स्थानीय न्यायधीश के पास इस पर कार्रवाई का अधिकार होगा।

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र कार्यक्रम शुरू:

- पेयजल एवं स्वच्छता और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 29 दिसम्बर 2016 से 'स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र' की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य देशभर में खुले में शौच मुक्त खंडों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूती प्रदान करना है।
- स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र का उद्देश्य देशभर के खुले में शौच मुक्त 708 खंडों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूती प्रदान करना है ताकि उन्हें कायाकल्प मानकों को पूरा करने के लिए उच्च स्तर की साफ सफाई एवं स्वच्छता हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके।
- इसी तरह से उद्देश्य उन ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाना है जहां कायाकल्प पुरस्कृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित हैं।
- पहल के तहत खुले में शौच मुक्त खंडों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें मजबूती प्रदान करके साफ सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के मानक को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

आईएसए फ्रेमवर्क समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी:

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के फ्रेमवर्क समझौते को 28 दिसम्बर 2016 को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी।

पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दुनिया के 121 देश ने पिछले साल 30 नवंबर को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित 21वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आईएसए का गठन किया था तथा इस समझौते पर सहमत हुए थे।
- इस साल नवंबर में मोरक्को के मराकेश में हुए 22वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इस समझौते को हस्ताक्षर के लिए पेश किया गया। मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व प्रभाव से इस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी गयी। अब तक 25 देश फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।
- आईएसए का उद्देश्य सौर ऊर्जा स्रोत संपन्न 121 देशों को इस क्षेत्र में सम्मिलित अनुसंधान, किफायती वित्त पोषण तथा सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए एक मंच पर लाना है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव स्थित ग्वाल पहाड़ी में बनाया जा रहा है। इससे भारत जलवायु तथा नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े मुद्दों के मामले में दुनिया में शीर्ष पर जायेगा।
- उल्लेखनीय है कि सरकार ने वर्ष 2022 तक देश में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के बाद वह दुनिया में सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता वाला देश बन जायेगा।

केन्द्र सरकार ने तिरूपुर रंगाई उद्योग के लिए 200 करोड़ रूपए मंजूर किए:

- भारत सरकार ने तिरूपुर रंगाई उद्योग के लिए 200 करोड़ रूपए की मंजूरी दी है। यह उद्योग देश में प्रथम शून्य तरलता निर्वहन (जेडएलडी) में भारी निवेश होने से गंभीर वित्तीय संकट के कारण बंद होने के कगार पर है।
- भारत सरकार ने तिरूपुर में रंगाई उद्योग की इस समस्या पर संज्ञान लिया और वस्त्र मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने सीईपी के प्रदर्शन के आधार पर अनुदान में परिवर्तित करने के लिए 18 सीईटीपी के लिए तमिलनाडु को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 200 करोड़ रूपए की मंजूरी दी है।
- इस कदम से सीईटीपी और 450 रंगाई इकाइयों को वित्तीय संकट से उबरने और 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग को प्राप्त करते हुए परियोजना को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी।

- तिरूपुर रंगाई उद्योग में 450 से ज्यादा रंगाई इकाइयों का कुल 1013 करोड़ रूपए की लागत से सीईटीपी समर्थ 18 जेडएलडी के रूप में सामूहिक रूप से गठन किया गया था। यह परियोजना एक वैश्विक मानक का रूप ले चुकी है और इसे पर्यावरणविदों और प्रसंस्करण उद्योग के लिए दुनियाभर से सराहा भी जा चुका है। हालाकि अपनी तरह की इस पहली परियोजना को तकनीकी चुनौतियों, लागत बढ़ने से बकाया ऋणों और अधूरी परियोजनाओं ने वित्तीय संकट में डाल दिया।
- तिरूपुर वस्त्र प्रसंस्करण और बुनाई उद्योग का एक केन्द्र है जो पांच लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करते हुए देश के वस्त्र निर्यात में 22 प्रतिशत का योगदान देता है।

आईवीआरएस प्लेटफॉर्म:

- कॉल ड्रॉप समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक इंटीग्रेटेड वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) सिस्टम लॉन्च कर दिया है। यह दिल्ली और मुंबई समेत कई स्थानों पर लॉन्च किया गया है ताकि कॉल इक्विटी पर सब्सक्राइबर्स की सीधी प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके।
- लोगों की प्रतिक्रियाओं को सीधे आपरेटर्स तक पहुंचाया जाएगा ताकि समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठाए जाएं और कॉल ड्रॉप के मुद्दे का समाधान किया जा सके। आधिकारिक रिलीज में बताया गया है कि आईवीआरएस प्रणाली को शीघ्र ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। सब्सक्राइबर्स को शॉर्ट कोड 1955 की ओर से एक आईवीआरएस कॉल प्राप्त होगा।
- उनसे यह पूछा जाएगा कि उन्हें उनके क्षेत्र में कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझना पड़ रहा है कि नहीं। इसमे आगे कहा गया है कि सब्सक्राइबर्स शार्ट कोड 1955 पर टोल फ्री एसएमएस भी भेज सकते हैं, जिसमे वो उस शहर, कस्बे और गांव का भी जिक्र कर सकते हैं जहां उन्हें बार-बार कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
- इस पहल पर टिप्पणी करते हुए संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि आईवीआरएस उपभोक्ताओं से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है और जनता की इस आवाज के माध्यम से उस सर्विस में सुधार किया जा सकता है जो उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है।

नेदुमकयाम देश की पहली कैशलेस आदिवासी कॉलोनी बनी:

- 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने के फैसले के बाद नकदी को लेकर लोगों को अभी भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में केरल की एक आदिवासी कॉलोनी को कैशलेस और डिजिटल घोषित किया गया है। नीलांबुर के इस कॉलोनी में शौचालय जैसी कई आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं इसके वाबजूद यह कॉलोनी देश के लिए रोल मॉडल बन गई है।
- नक्सलियों से खतरा का सामना करने वाले इस कॉलोनी के लोग डिजिटल भुगतान के लिए तैयार हैं। जिलाधिकारी अमित मीणा ने नेदुमकयाम को 27 दिसम्बर 2016 को पहली डिजिटल और कैशलेस आदिवासी कॉलोनी घोषित की।
- इस घोषणा से पहले कॉलोनी के लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन और डिजिटल भुगतान के बारे में एक सप्ताह तक प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान कॉलोनी के लोगों ने स्मार्टफोन की मदद से जिलाधिकारी के खाते में 5-5 रुपये भेजे। फिर उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से उनको 25-25 रुपये लौटाए।
- यह कॉलोनी कारूलयी पंचायत के अंतर्गत आती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद पी वी अब्दुल बहाव ने इसे गोद लिया हुआ है। कॉलोनी के सामुदायिक केंद्र पर जन शिक्षण संस्थान ने वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी है। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के लिए एक साल के लिए एक आदिवासी स्वयंसेवक को लगाया गया है।

चीन ने पर्यावरण टैक्स लगाया

- चीन ने प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए 26 दिसम्बर 2016 को पर्यावरण संरक्षण के लिए संसद में कानून पारित कर उद्योगों को खासतौर पर निशाना बनाते हुए हैवी इंडस्ट्रीज पर पर्यावरण कर लगाने का फैसला लिया है।

- चीन की राजधानी बीजिंग सहित कई शहरों में धुंध एक बार फिर से छा गई है। पेइचिंग के आसपास के प्रांतों को प्रदूषण की वजह से एक सप्ताह तक रेड अलर्ट का सामना करना पड़ा था।
- इसी वजह से वहां स्कूलों को बंद किया गया था और वाहनों को रेग्युलेट करने के लिए आॅड-इवेन सिस्टम लागू किया गया था। यह कानून चीन में 1 जनवरी 2018 से प्रभाव में आ जाएगा।

अग्नि 5 का सफल परीक्षण:

- 26 दिसम्बर 2016 को भारत की सर्वाधिक लंबी रेंज वाली इंटरकॉन्टीनेंटल मिसाइल अग्नि-5 मिसाइल का ओडिशा के अब्दुल कलाम आईलैंड से सफल परीक्षण किया गया।
- पूर्व में जनवरी 2015 में इसका परीक्षण किया गया, तब इसमें मामूली तकनीकी कमियां सामने आई। इन कमियों को ख़त्म करने के बाद मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अग्नि-5 की जद में पाकिस्तान, चीन और यूरोप समेत आधी दुनिया है।
- इंटरकॉन्टीनेंटल मिसाइल अग्नि-5 का परीक्षण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) की देखरेख में किया गया।
- इंटरकॉन्टीनेंटल मिसाइल अग्नि-5-> 6000 किमी रेंज वाली यह मिसाइल एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है।

सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड का उद्घाटन :

- केन्द्रीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 26 दिसम्बर 2016 को कहा कि बंदरगाह आधारित विकास और रोजगार सृजन को गति देने के लिए शुरू की गयी सागरमाला परियोजना में करीब 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे लगभग तीन करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
- गडकरी ने इस परियोजना के लिए वित्तपोषण एवं सहयोग के लिए विशेष इकाई सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड का शुभारंभ करने के बाद कहा कि बंदरगाह आधारित विकास एवं रोजगार सृजन के लिए सागरमाला के चार प्रमुख स्तम्भ – बंदरगाह आधुनिकीकरण एवं नये बंदरगाह का विकास, बंदरगाह कनेक्टिविटी, बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण तथा तटीय समुदायों का विकास शामिल है।
- उन्होंने कहा कि सागरमाला परियोजना में 12 लाख करोड़ से लेकर 15 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश होगा। यह परियोजना वर्ष 2035 तक के लिए है, लेकिन इसके वर्ष 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इसके तहत राष्ट्रीय समृद्धि योजना शुरू की जायेगी जिसके तहत आठ लाख करोड़ रुपये लागत की 400 परियोजनायें होंगी। इनमें से एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनायें शुरू हो चुकी हैं।